

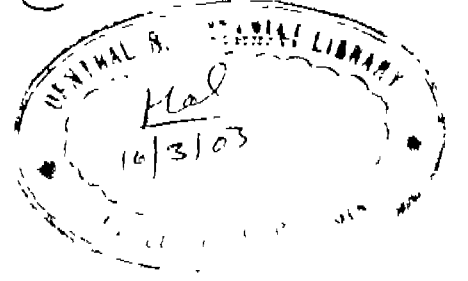


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 159]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2002/आषाढ़ 6, 1924

No. 159]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2002/ASADHA 6, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2002

अंतिम जांच परिणाम

विषय : ताईवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, यूएई, सिंगापुर तथा थाइलैंड मूल की अथवा वहां से

निर्यातित बाइएक्सली ओरिएन्टेड पोली प्रोपीलीन फिल्म (बी ओ पी पी) के आयातों से संबंधित

पाटनरोधी जांच- अंतिम जांच परिणाम ।

21/1/2001-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाइप वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम 1995 को ध्यान में रखते हुए

क. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके पश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने ताईवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, यूएई, सिंगापुर तथा थाइलैंड मूल के अथवा वहां से निर्यातित बाईएक्सली ओरिएन्टेड पोली प्रोपीलीन फिल्म (बी ओपीपी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में दिनांक 30 मई 2001 की अधिसूचना संख्या 21/1/2001 डी जी ए डी द्वारा जांच की शुरुआत को अधिसूचित किया तथा हितबद्ध पार्टियों से सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया और इस

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया ।

- (ii) प्राधिकारी ने ताईवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, यूएई, सिंगापुर तथा थाइलैंड मूल की अथवा वहा से निर्यातित बाइएक्सली ओरिएन्टेड पोलि प्रोपीलीन फिल्म (बी ओ पी पी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में दिनांक 14 अगस्त 2001 की अधिसूचना सं. 21/1/2001 डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए तथा हितबद्ध पार्टियों को इस अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।
- (iii) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति भेजी जिन्हें इस पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने विचार यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।
- (iv) प्राधिकारी ने इस अनुरोध के साथ नई दिल्ली स्थित इंडोनेशिया, ओमान, यूएई, सिंगापुर, थाइलैंड के दूतावासों, ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली तथा हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, एच के को प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति भी भेजी कि वे प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने विचार प्रस्तुत करें ।
- (v) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों की मौखिक रूप से सुनवाई करने के लिए 21 नवम्बर 2001 को सार्वजनिक सुनवाई की थी जिसमें घरेलू उद्योग निर्यातकों और आयातकों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे । सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित हुई पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम में हितबद्ध पार्टियों से इस प्रकार प्राप्त हुए लिखित अनुरोधों पर विचार किया है ।
- (vi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को अनुरोध पर सभी हितबद्ध पार्टियों के लिए निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखा ।
- (vii) प्रारंभिक जांच परिणामों की घोषणा से पूर्व हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, जिन्हें पहले अधिसूचित किए गए प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रकाशित किया गया है, को संक्षिप्तता की वजह से इसमें दोहराया नहीं गया है । तथापि, हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर प्रारंभिक जांच परिणामों में और/अथवा इन जांच परिणामों में समुचित कार्रवाई की गई है ।

- (viii) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यो/आधार का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को किया गया था और इन पर प्राप्त टिप्पणियां पर भी इन जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया था ।
- (ix) यह जांच 1 अप्रैल 1999 से 30 सितम्बर 2000 तक की अवधि के लिए की गई थी ।
- (x) प्राधिकारी ने कीमत संबंधी वचन पत्र से संबंधित मुद्दों और अनुरोधों के बारे में संबंधित हितबद्ध पार्टियों को सुना और उनसे विचार विमर्श किया ।
- (xi) प्राधिकारी को दो घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै. मैक्स इंडिया और सुप्रीम ओरिएन्टेड से क्षति एवं लागत संबंधी सूचना प्राप्त हुई । आगे मै. अल खलीज, ओमान से प्रश्नावली संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी । प्राधिकारी ने दोनों सूचनाओं को स्वीकार किया यद्यपि सूचनाएं प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद प्राप्त हुई थे । निर्यातक द्वारा उठाए गए मुद्दे इन जांच परिणामों में प्रकाशित किए गए । इसके अलावा घरेलू उत्पादकों ने क्षति एवं लागत संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है ।
- (xii) *** यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना गया है ।
- (xiii) इस पाटन रोधी जांच को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने 17.6.2002 के का.ज्ञा.सं. 354/155/2001 टी आर यू के तहत 30.5.2002 से एक माह की अवधि के लिए समय वृद्धि प्रदान की थी ।

(ख) **याचिकाकर्ताओं/निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार तथा प्राधिकारी द्वारा जांच**

2. याचिकाकर्ता, निर्यातकों और आयातकों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनका संक्षेप से उल्लेख निम्नानुसार है:-

2.1 घरेलू उद्योग के विचार

(क) विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है कि वे प्रकटन विवरण का समर्थन करते हैं कि सभी प्रकार की बी ओ पी पी फिल्में वर्तमान जांच के दायरे में नहीं हैं ।

ओ पी पी फिल्म और अन्य बी ओ पी पी फिल्म समान उत्पाद हैं। इसके समर्थन में उन्होंने समान उत्पाद, यर्थात् पोलिस्टर फिल्म के बारे में यूरोपीय आयोग के जांच परिणामों का हवाला दिया है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि धातुकृत बी ओ पी पी फिल्म को अलग रखने तथा इन फिल्मों तथा बेस फिल्मों की अलग तुलना करने का निम्नलिखित कारणों से कोई औचित्य नहीं है जैसा कि यूरोपीय आयोग ने अपने जांच परिणामों में स्पष्ट किया है:-

- (i) धातुकरण प्रक्रिया में अल्युमिनियम जैसी धातु को मिलाया जाना शामिल होता है और इससे पॉलीस्टर फिल्म की मूलभूत भौतिक तकनीकी एवं रासायनिक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता है।
- (ii) यह तथ्य कि धातुकृत पालिस्टर फिल्म के उत्पादन संबंधी अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत होती है (और इसकी परिणति उच्चतर उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में होती है)। कोई ऐसा तत्व नहीं है जिससे कुछेक प्रकार को कार्रवाई के क्षेत्र से बाहर रखे जाने को न्यायाचित ठहराया जा सके।
- (iii) केवल धातुकरण का कार्य करने वाली कंपनियां बेस पालिस्टर फिल्म का उत्पादन नहीं करती हैं और उसकी खरीद अलग अलग स्रोतों से की जाती है। तत्पश्चात् खरीदी गई पालिस्टर फिल्म का इन धातुकर्मियों द्वारा धातुकरण किया जाता है। तथापि, उनके द्वारा की गई प्रसंस्करण संबंधी कार्रवाई पालिस्टर फिल्म के सामुदायिक उत्पादकों के रूप में उन पर विचार करने के लिए स्वतः ही पर्याप्त नहीं है।
- (iv) बेस पालिस्टर फिल्म के मात्र प्रसंस्करण (धातुकरण) से उत्पाद की मूलभूत भौतिक तकनीकी एवं रासायनिक विशेषताएं नहीं बदलती हैं।

(ख) घरेलू उद्योग के आधार के बारे में

जहां तक आधार के निर्धारण का संबंध है उन्होंने अनुरोध किया है कि जांच की शुरुआत के समय पर भी याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने के आधार को पूरा करते थे। यह याचिका एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है। निम्नलिखित उत्पादक उक्त एसोसिएशन के सदस्य हैं:

मै. फ्लैक्स इंडस्ट्रीज लि०, गुजरात प्रोपैक, कोरमो फिल्म लि०, एक्सप्रो इंडिया लि०, मैक्स इंडिया लि०, सुप्रीम ओरिएन्टेड ।

बी ओ पी पी फिल्मों के निम्नलिखित उत्पादक उक्त एसोसिएशन के सदस्य नहीं है । मै. एम एम रबड़, मै. कबड़ा प्लास्टिक्स, एमपीयू पी यू एल उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि मै. कबड़ा प्लास्टिक्स संबद्ध वस्तु का एक आयातक (या आयातकों से संबंधित) है ।

एसोसिएशन की कार्यकरिणी समिति ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष बी ओ पी पी फिल्मों के आयातों पर उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर करने का पहले निर्णय लिया था । उक्त निर्णय एसोसिएशन की उपविधियों के अनुसार लिया गया था । इस प्रकार उक्त याचिका बी ओ पी पी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी और फ्लैक्स इंडस्ट्रीज लि., गुजरात प्रोपैक लि., मैक्स इंडिया लि० और सुप्रीम ओरिएन्टेड फिल्म लि० द्वारा उसका विशिष्ट रूप से समर्थन किया गया था । समर्थनकर्ता कंपनियां के समर्थन से भागीदार कंपनियों का उत्पादन जांच की शुरुआत के समय पर भी पात्र भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक बनता था ।

उन्होंने आगे यह उल्लेख किया है कि निर्यातक द्वारा दिए गए तर्क का यह अर्थ निकलेगा कि “निर्दिष्ट प्राधिकारी को पहले जांच करनी चाहिए और इसके बाद जांच की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए ।’ तथापि उनका तर्क यह है कि यह जांच हेतु कार्रवाई है ।

(ग) जांच की अवधि के बारे में

निर्यातकों द्वारा जांच अवधि के बारे में दिया गया समूचा तर्क अनदेखी करने योग्य है । इस संबंध में निम्नलिखित बातें संगत हैं:

नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के बारे में निर्णय पारित करने की कोई जरूरत नहीं है । न तो इस हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र-नियम 5(2) न ही जांच को

शासित करने वाले सिद्धांतों नियम 6 और न ही प्रारंभिक जांच परिणामों की अपेक्षा नियम 12 में इसका उल्लेख है। इस प्रकार का मामला होने के कारण समूचा तर्क आधारहीन और विधि के असंमत है।

यद्यपि जांच अवधि के निर्धारण हेतु वित्त वर्ष, लेखा वर्ष और व्यापार चक्र पर विचार किया जा सकता है तथापि यह अनुरोध है कि यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि ये जांच अवधि के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। इस बात को नहीं देखा गया है कि नव भारत में ही अलग अलग कंपनियों का लेखा वर्ष अलग अलग हो सकता है। (उदाहरणार्थ वर्तमान जांच में ही दो भागीदार कंपनियों के लेखा वर्ष अलग अलग थे) तो संबद्ध देशों के निर्यातकों की बात ही अलग है।

प्रशासनिक सुविधा के मद्देनजर "पाटन एवं क्षति" के प्रमुख मुद्दे की अनदेखी नहीं की जा सकती। जांच अवधि का निर्धारण "घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन" द्वारा की जाएगी और न कि प्रशासनिक सुविधा द्वारा ऐसा करना इस तर्क को दिए जाने के समान है कि अस्पताल की प्रशासनिक सुविधा और न कि रोगी की बीमारी यह तय करेगी कि क्या और कब रोगी की शल्य चिकित्सा की जानी चाहिए।

(घ) पाटन के बारे में

वर्तमान जांच में केवल एक निर्यातक ने उत्तर दिया है। उक्त निर्यातक ने प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद उत्तर दिया है। घरेलू उद्योग इस प्रकार के विलंबित उत्तर को स्वीकार किए जाने के बारे में बहुत चिंतित है जिससे घरेलू उद्योग के हितों को नुकसान पहुंच रहा है और जो निर्यातकों के हित में है। इस संबंध में यूरोपीय संघ और यूएसए की प्रक्रियाओं पर भरोसा किया जा रहा है जिनमें प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद किसी निर्यातक का कोई उत्तर स्वीकार नहीं किया जाता है।

निर्यातक यह दोहराते हैं कि निर्यातक द्वारा दायर किए गए उत्तर को निम्नलिखित अन्य कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

1. उत्तर का समर्थन अर्थपूर्ण गोपनीय सारांश द्वारा नहीं किया गया है।
2. परिशिष्ट 1 (घरेलू बाजार में बिक्रियों से संबंधित) परिशिष्ट 2 (भारत को निर्यात) और उत्पादन लागत के बारे में सूचना का गोपनीय सारांश सूची के आधार पर उपलब्ध नहीं किया गया है।

सुधार संबंधी प्रमाण पत्र जैसी सूचना भी गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार समूचे विश्व के अन्य जांच प्राधिकारियों की प्रक्रिया के अनुसार समूचा उत्तर अस्वीकार है।

3. घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में निर्यातक के खैए से चिंतित है। यह स्थिति निर्यातक द्वारा चयनात्मक आधार पर सहयोग देने की है।
4. उपर्युक्त के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के बारे में उन्होंने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं
 - (i) आरंभिक/प्रथम/द्वितीयक के रूप में उत्पाद की ग्रेडिंग उत्पादन के बाद उत्पाद का मात्र वर्गीकरण है। इन सभी प्रकारों के उत्पादन की लागत वही रहती है। जहां पुनः प्रसंस्करण करने योग्य उत्पादन की केवल अनदेखी किए जाने की आवश्यकता है और केवल निवल बिक्री योग्य उत्पादन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वहीं हम मानते हैं कि निर्यातक द्वारा पुनः प्रसंस्करण करने योग्य उत्पादन पर विचार करते हुए उत्पादन की लागत निर्धारित की गई प्रतीत होती है। यदि यही मामला है तो यह अनुरोध है कि उत्पादन की लागत का निर्धारण निवल बिक्री योग्य उत्पादन के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।
 - (ii) जब तक निर्यातक सैकेन्ड्स/बी ग्रेड के रूप में माल की बिक्री करता है और जोकि बीजक से स्पष्ट होता है तब तक उक्त दावा अस्वीकार्य है।
 - (iii) क्या सैकेन्ड्स की बिक्री कीमत की तुलना उत्पादन की लागत से की जानी चाहिए, इसका तात्पर्य यह होगा कि ऐसी बिक्रियां उत्पादन की लागत से कम पर की गई थीं (ऐसी सैकेन्ड्स की बिक्री सामान्यतया आरंभिक उत्पाद की कीमतों से काफी कम पर की जाती हैं) ऐसे मामलों में ऐसी स्थिति में सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत उपर्युक्त लाभ के आधार पर किया जाता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों प्रकारों का पाटन हुआ है।

- (iv) क्या यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि निर्यातक ने दोनों बाजारों में भिन्न भिन्न ग्रेडों की बिक्री की है, इसका तात्पर्य यह होगा कि निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण दोनों ग्रेडों के लिए संचयी रूप से औसत आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

ड.) क्षति के संबंध में

जहां तक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संबंध है, इस बारे में पहले किए गए अपने अनुरोधों को वे दोहराते हैं। उन्होंने पहले ही पर्याप्त सूचना प्रदान की है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है इसे प्रकटन विवरण में भी स्वीकार किया गया है। वे अनुरोध करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति को दर्शाते हैं:

संबद्ध देशों से हुए आयातों के बाजार हिस्से में समग्ररूप से और भारत में आयात तथा खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्रियों तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग को अपनी लागतों के प्रभाव में पर्याप्त कमी के बावजूद उत्पाद की प्रति इकाई में वित्तीय हानियां हुई हैं।

उद्योग ने अपने उत्पादन को बेचने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। तथापि लाभ की बात तो दूर, उद्योग अपनी उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं कर सका है।

संबद्ध देशों से निर्यात कीमत में काफी कमी की गई है। इसके परिणाम स्वरूप आयात के पहुंच मूल्य में की गिरावट आई है। निर्यात कीमत में कमी भारतीय रूपए के मूल्य में वृद्धि के बावजूद हुई थी।

संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम थी, जिससे भारतीय बाजार में कीमत में अत्यधिक कटौती हुई थी। वास्तव में आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में पहले कोई कमी नहीं हो रही थी। तथापि, आयातों ने 1999-2000 से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी करना शुरू कर दिया था जिनमें जांच की अवधि में और वृद्धि हो गई। इससे घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन की लागत वसूली करने में रूकावट आई।

सभी मापदंड संचयी और समग्र रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

च) निर्धारित धन राशि के आधार पर शुल्क

अनुरोध है कि संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत कच्चे माल की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त, अन्य पेट्रो-रसायन के उत्पादों की कीमतों के अनुसार कच्चे माल की कीमतों में भी परिवर्तन होता रहता है। उपर्युक्त के मद्दे नजर अनुरोध है कि निर्धारित राशियों के रूप में पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण यू एस डालर में किया जाए।

2.2 मै. अल खालीज प्रोली प्रोपीलीन प्रोडक्ट्स कंपनी साओग, ओमान सल्तनत

क) विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तुओं के बारे में

जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा तथा जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में बताया गया था, विचाराधीन उत्पाद अस्पष्ट तथा अति व्यापक है। याचिकाकर्ताओं के तर्कों तथा जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना तथा प्रारंभिक जांच परिणामों की विषय वस्तु से यह पर्याप्ततः स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की बी ओ पी पी फिल्में तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। अतः पाटनरोधी नियमों के तहत बी ओ पी पी फिल्मों के सभी प्रकारों को समान वस्तुएं मानना उपयुक्त नहीं होगा।

निर्यातक ने तर्क दिया है कि धातुकृत बी ओ पी पी फिल्म को बी ओ पी पी फिल्म के समान वस्तु नहीं मानना चाहिए क्योंकि धातुकरण की प्रक्रिया से एक नया उत्पाद बनता है जिसका अलग नाम विशेषता तथा उपयोग होता है। इसके समर्थन में निर्यातक ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर सीमाशुल्क बोर्ड के दो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं (प्रतिलिपि संलग्न) जो भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर आधारित हैं अतः बाध्यकारी हैं। निर्यातक ने दावा किया है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार धातुकृत बी ओ पी पी फिल्म साधारण बी ओ पी पी फिल्म की तुलना में भिन्न उत्पाद है अतः इन्हें एक ही श्रेणी में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। धातुकृत बी ओ पी पी फिल्म को आदितः जांच का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था।

ख) घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में

निर्यातक ने बताया है कि जहां तक आधार का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच की शुरुआत के समय पर अंतिम निर्धारण करना होता है। यह जांच को न्यायसंगत ठहराने के लिए नियम 5(3) (ख) के तहत परिकल्पित पर्याप्ता की जांच के विरुद्ध है। इस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में किसी भी निर्धारण को दर्ज नहीं किया है। अतः निर्यातक ने अनुरोध किया है कि मामले को डब्ल्यू टी ओ पैनल के अनेक निर्णयों के अनुसार समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मूल कमी को अब दूर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया था आधार के बारे में किसी भी प्रकार का निर्धारण अत्यंत त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का विवरण जांच शुरुआत के समय स्वयं ही अस्पष्ट था।

ग) जांच अवधि के बारे में

उन्होंने बताया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा व्यापक जांच करने हेतु 18 माह की अवधि का प्रस्ताव किया है और उसे माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कुछेक कारणों से स्वीकार कर लिया था परन्तु इसके कारण न तो याचिका सार्वजनिक फाइल और न ही प्रारंभिक जांच परिणामों में उपलब्ध हैं। यद्यपि जांच की अवधि के रूप में कोई विशेष अवधि चुनने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्ति पर कोई रोक अथवा सीमा नहीं है परन्तु यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं हो सकता कि सामान्यतया इस अवधि को चयन विश्व भर में आर्थिक या वित्तीय कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है। कुछेक विचार जिनमें जांच की अवधि का विकल्प प्रभावित होता है, उनमें शामिल हैं वित्तीय वर्ष, व्यापार चक्र का कलेंडर वर्ष सामान्यतया वित्तीय वर्ष को जांच की अवधि के रूप में दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रशासनिक सुविधा के साथ साथ सभी प्रकार के मौसमों के उतार चढ़ावों को ध्यान में रखा जाता है। तथापि यदि घरेलू उद्योग इस बात का प्रदर्शन करता है कि जांच की अवधि अधिक लेने की आवश्यकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास पूरा लेखा वर्ष या उसकी कुछेक तिमाहियों को लेने की पद्धति से हट कर चलने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए।

घ) क्षति के बारे में

घरेलू उद्योग के केवल 47.8% को हिसाब में लेने के बाद क्षति का विश्लेषण करना गलत है, खासकर तब जब याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया हो कि याचिका एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है और यह कि वे अन्य उत्पादकों का भी प्रतिनधित्व करते हैं ।

च) प्रकटन विवरण के संबद्ध मै. अल खलीज के विचार

1. प्रकटन विवरण में यह बताया गया है कि धातुकरण प्रक्रिया में अल्यूमीनियम जैसी धातु को मिलाया जाता है और उससे पोलिस्टर फिल्म की मूलभूत भौतिक तकनीकी तथा रासायनिक विशेषताएं परिवर्तित नहीं होती है । यह सी बी ई सी के उस परिपत्र के प्रत्यक्षतः प्रतिकूल में है जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि बेयर फिल्मस को लेकट्ड लैलीनेटिड या बेयर फिल्मस में परिवर्तन करने से एक नए उत्पाद का विनिर्माण होता है जिसका एक अलग ही नाम विशेषता और उपयोग होते हैं ।
2. यह नोट किया जा सकता है कि सी बी ई सी का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों तथा विधि मंत्रालय की राय पर आधारित है । यह बहुत आश्चर्यजनक होगा कि यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ई सी के अनुहत निर्णय पर निर्भर रहने का विकल्प चुनते हैं जब उस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा विधि मंत्रालय की राय के आधार पर स्पष्ट रूप से निर्णय लिया जा चुका है ।
3. प्रकटन विवरण पत्र के पैरा 1.7(ii) में यह भी बताया गया है कि यह तथ्य कि उत्पादन संबंधी अतिरिक्त प्रक्रिया धातुकृत पोलिस्टर फिल्म के उत्पाद के लिए आवश्यक है (इसकी परिणति उत्पादन की अधिक लागत तथा अधिक बिक्री कीमत में होती है) ऐसा तत्व नहीं है जिससे कार्रवाई के क्षेत्र से कुछेक प्रकार को बाहर रखे जाने को न्यायोचित ठहराया जा सके । ई सी के मामले की स्थिति भारत के मामले की तुलना में भिन्न है । स्पष्टया ई सी के मामले में मुद्दा धातुकृत फिल्म को शामिल न करने का था । अतः ई सी के निर्णय को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि जांच शुरुआत संबंधी सूचना में शिकायत में किए गए दावों, जांच के क्षेत्र के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अवगत न कराया जाए । भारतीय निर्यातकों द्वारा किए गए तर्कों का मामले पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है जिसकी प्रति दिनांक 9 और 10 मई, 2002 के हमारे पत्रों के बावजूद हमें नहीं भेजी गई है । यह न्यायके प्रति विडम्बना की बात होगी यदि ई सी के किसी निर्णय पर ई सी के उक्त निर्णय संबंधी कागजात तथा पृष्ठभूमि को देखे बिना हम अपने उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को प्राथमिकता देने की बजाय उस पर भरोसा करें । उपर्युक्त के होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि ई सी का मामला इस मामले से भिन्न था क्योंकि उक्त मामले में शुरुआत में धातुकृत फिल्म को शामिल नहीं किया गया था जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों से स्पष्ट होता है ।

4. ऐसा न तो घरेलू उद्योग का और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी का इरादा था कि मैटेलाइज्ड बीओपीपी फिल्म को जांच के दायरे में रखा जाए जैसाकि निम्नलिखित के द्वारा पता चलता है :-

(क) प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 4.1.3 में 'बीओपीपी फिल्मों का उपयोग मुख्यतः पैकेजिंग उद्योग द्वारा किया जाता है, इसका उपयोग प्रमुखतया पैकेजिंग एडहैसिव टेप्समैटेलाइजिंग इत्यादि में किया जाता है ।'

यह अनुरोध किया गया था कि मैटेलाइज्ड बीओपीपी फिल्मों का प्रयोग आगे मैटेलाइजिंग में नहीं किया जा सकता और इसलिए वे फिल्में जो पहल ही मैटेलाइज्ड हैं, उन पर विचाराधीन उत्पाद के एक भाग के रूप में विचार नहीं किया जा सकता ।

(ख) प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 4.1.3 में यह उल्लेख किया गया है कि 'बीओपीपी फिल्म का उत्पादन निष्कर्षण प्रक्रिया द्वारा किया जाता हैपोलाप्रोपिलिन का निष्कर्षण बीओपीपी फिल्म प्राप्त करने के लिए किया जाता है । यद्यपि प्रारंभिक जांच परिणामों के विचाराधीन उत्पाद को इस भाग में भी यह स्पष्ट किया गया था कि केवल निष्काशित उत्पादों को ही शामिल किया जाना है तथापि घरेलू उद्योग और साथ ही साथ माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह मंशा नहीं थी कि मैटेलाइज्ड बीओपीपी फिल्मों को जांच के दायरे में शामिल किया जाए ।

(ग) यह तथ्य कि मैटेलाइज्ड बीओपीपी फिल्मों को जांच के दायरे में नहीं रखा गया है याचिका दायर करने वाले घरेलू उद्योग की स्थिति के निर्धारण से भी स्पष्ट है । याचिका और प्रारंभिक जांच परिणामों को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग के आधार की जांच करने के प्रयोजनार्थ अनेक अलग किस्म के मैटेलाइजर्स पर विचार नहीं किया गया था । उनकी सूचना के अनुसार, देश में लगभग 29 विशेष मैटेलाइजर हैं । मैटेलाइज्ड फिल्मों के लिए बीओपीपी दरें भी भिन्न हैं । तथापि, यदि, माननीय प्राधिकारी यह मानते हैं कि मैटेलाइज्ड बीओपीपी फिल्मों को जांच के दायरे में शामिल किया गया था तो अनुरोध है कि याचिका दायर करने के लिए घरेलू उद्योग के आधार का आरंभिक निर्धारण ही त्रुटिपूर्ण होगा ।

(घ) यह नोट करना भी रोचक है कि अपने लिखित अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने यह 'स्पष्ट' किया है कि मैटेलाइज्ड बीओपीपी फिल्में उनके द्वारा दायर याचिका के दायरे में आती हैं । माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात को जानते होंगे कि पास्टनरोधी विधि

शास्त्र में जांच के दायरे को बढ़ाने की अनुमति नहीं है। अतः हमारा अनुरोध है कि उपरोक्त तर्कों से अनन्य एवं बहुविधि रूप से यह प्रमाणित होता है कि मेटेलाइज्ड बीओपी फिल्मों को आदितः जांच का अंग नहीं बनना था।

क्षति के बारे में

(क) घरेलू उद्योग को परिभाषा के प्रथम भाग में परिभाषित किया गया है ताकि समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी गतिविधि में लगे समूचे उत्पादकों को शामिल किया जा सके। इसमें आगे यह कहा गया है कि विकल्पतः घरेलू उद्योग में उन घरेलू उत्पादकों का उल्लेख किया जा सकता है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। अतः हमारा अनुरोध है कि केवल 47.8 % पर आधारित क्षति संबंधी विश्लेषण अनुचित है क्योंकि 50% से कम की कोई भी वस्तु एक बड़ा भाग नहीं बनती है। मुद्दे की वैधता के अलावा, हमने निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस बात पर विचार करने का अनुरोध किया था कि समूचे घरेलू उद्योग के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए घरेलू उद्योग के एक छोटे भाग की सूचना का विश्लेषण करना आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः अनुचित होगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए उन उत्पादकों की वित्तीय स्थिति की जांच करने की भी जरूरत है जो केवल 'समर्थन' कर रहे हैं; किंतु जो तथाकथित याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का भाग नहीं हैं। ऐसा उपरोक्त संदर्भ में था कि हम इस बात पर जो दे रहे हैं कि घरेलू उद्योग को पूर्ण प्रकटन विवरण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जाए ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निष्पक्ष एवं उचित जांच परिणामों पर पहुंच सकें। इसका कारणात्मक संबंध के मुद्दे पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

(ख) जहां तक आयातों की मात्रा का संबंध है प्रारंभिक जांच-परिणामों में यह उल्लेख किया गया था कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई है आगे यह माना गया था कि प्रतिशत के रूप में भी मात्रा में वृद्धि हुई है। बाजार हिस्से एवं पहुंच लागत के बारे में भी इसी प्रकार का विश्लेषण किया गया था।

(ग) कृपया यह स्मरण करें कि निर्यातकों ने यह अनुरोध किया था कि जांच अवधि के आंकड़ों की तुलना 1997-98 के आंकड़ों के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि उचित विश्लेषण के लिए यह अपेक्षित होगा कि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के साथ तब तक तुलना की जाए जब तक कि इसके विरुद्ध इसके कारणों का उल्लेख न किया जाए। ऐसा मामला न होने के कारण इन कारणों की वजह से क्षति संबंधी जांच-

परिणामों पर पुनः गौर करने की जरूरत है क्योंकि उचित विश्लेषण से पूर्णतः अलग तस्वीर उभर कर आएगी। उपरोक्त के अलावा, निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान पूर्णतः गलत परिणाम निकालने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सूचना के गलत प्रस्तुतीकरण की ओर आकर्षित किया था। घरेलू उद्योग ने उचित तुलना करने के लिए स्पष्टतौर पर 18 महीनों के आंकड़ों को 'वार्षिक' आधार पर प्रस्तुत किया था। माननीय प्राधिकारी इस बात से सहमत होंगे कि जब 8 महीनों की अवधि में से 12 महीनों के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हों तो केवल 6 महीनों के आंकड़ों को ही वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना होता है। हमने 1999-2000 के वास्तविक आंकड़ों तथा 2000-01 के प्रथम 6 महीनों के आंकड़ों को वार्षिक आधार पर लेने के बाद विश्लेषण किया था, दोनों ही अवधियां जांच-अवधि की अंग हैं। जांच-अवधि के अंतिम 6 महीनों के दौरान संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा 54.4% से घटकर वस्तुतः 30.4% (वार्षिक) हो गया था। इसी अवधि के दौरान मांग के प्रतिशत के रूप में भी बाजार हिस्सा 4.2% से घटकर 1.2% हो गया है।

ग. आयातकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार

2.3 मै0 न्यू पैक प्लास्टिक प्रा0 लि0:

पाटन-रोधी जांच शुरू किए जाने के कारण बीओपीपी फिल्म की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है यद्यपि पोलीप्रोपीलिन की कीमतों में गिरावट आ रही है।

हमारे देश में बीओपीपी फिल्म का आयात कुल मांग का केवल 6.37% हुआ है। आयातों की ऐसी अल्प मात्रा को बीओपीपी फिल्म का पाटन नहीं कहा जा सकता जबकि बीओपीपी फिल्म की भारतीय मांग के 93.63% भाग की पूर्ति घरेलू विनिर्माताओं द्वारा की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बीओपीपी फिल्म (टेप ग्रेड) की कीमत लगभग 1.20 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. (लगभग 57.60 ₹) की है और यहां तक कि भारतीय फिल्म विनिर्माताओं द्वारा इसी निर्यात कीमत की पेशकश की जा रही है जबकि घरेलू बाजार में वे 98 ₹ प्रति किग्रा० की कीमत की पेशकश कर रहे हैं।

उपरोक्त को देखते हुए, उन्होंने अनुरोध किया है कि पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

उपयोक्ता एसोसिएशनों के विचार

2.4. मै0 पेपर, फिल्म एण्ड फॉयल कन्वर्टरस एसोसिएशन, बंबई में

क्षति के बारे में

निर्यात कीमतें भारतीय उत्पाद की कीमतों से काफी कम नहीं हैं। भारतीय उद्योग का उत्पादन 20% तक बढ़ा है।

वर्ष 1999-00 की तुलना में 2000-01 के दौरान याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता सहित कुछेक कम्पनियों की लाभप्रदता में भारी वृद्धि हुई है।

लगभग प्रत्येक कम्पनी ने अपनी क्षमता के उपयोग में वृद्धि की है। जो 70% अथवा उससे अधिक का क्षमता उपयोग प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं, वे लाभ कमा रहे हैं। भारतीय उद्योग की क्षमता के उपयोग में वृद्धि होने से बिक्री में वृद्धि हुई है जिससे लाभ प्राप्त हुआ है।

घरेलू उद्योग के आधार के बारे में

याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल उत्पादन का केवल 47% बनता है और इसलिए सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (अधिसूचना 2/95-सी.शु.(गै.ट.) दिनांक 1.1.1995) के नियम 2(ख) के अनुसार याचिकाकर्ता को 'घरेलू उद्योग' के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता।

अन्य उपयोक्ता

मै0 जुरग्यान इंडस्ट्रीज, जबलपुर, मै0 जयपुर टिशूज, जयपुर, मै0 अंकित पैकेजिंग लिमिटेड, सिकन्दराबाद, मै0 नैशनल एडहैसिव्स, नई दिल्ली, मै0 पी0 जी0 इंडस्ट्रीज, ग्वालियर, मेघना लैमिनेट्स, मुम्बई और मै0 विन्डसर पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

प्रारंभिक जांच-परिणामों के उत्तर में हितबद्ध पक्ष, जो मुख्यतः बी ओ पी पी फिल्म -सैल्फ एडहेसिव टेप के उपयोक्ता हैं - पाटनरोधी शुल्क लागू करने का विरोध कर रहे हैं । संक्षेप में, निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :-

1. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से घरेलू रूप से बी ओ पी पी फिल्म की कीमतों में वृद्धि हुई है यद्यपि पोलिप्रोपीलीन (जोकि बी ओ पी पी फिल्म की प्रमुख कच्ची सामग्री है) की कीमतें घट रही है ।
2. यह बी ओ पी पी फिल्म के विनिर्माताओं द्वारा हजारों एस एस आई इकाइयों की कीमत पर मुनाफाखोरी का स्पष्ट मामला है ।
3. जोकि याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता को मै0 गुजरात प्रोपेक मो मै0 कौसमो फिल्मस द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है ।
4. याचिकाकर्ताओं के अलावा बी ओ पी पी फिल्म के अन्य विनिर्माता जैसे मै0 कौसमो फिल्मस, मै0 एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड लाभ कमा रहे हैं ।

मै0 एडहेसिव टेप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए)

उपयोक्ताओं ने यह बताया है कि अधिकांश जरूरतें भारतीय विनिर्माताओं द्वारा पूरी की जाती है ।

कम मात्रा में आयात की गई देशी बी ओ पी पी फिल्म (एडहेसिव टाइप ग्रेड) की खपत की तुलना में बीओपीपी फिल्म का अल्प मात्रा में हुआ आयात 0.4% से कम बनेगा । इससे कोई पाटन प्रदर्शित नहीं होता है ।

भारत में घरेलू विनिर्माताओं ने एक कार्टल का गठन किया है और वे अपनी फिल्म की बिक्री कीमत में लगातार वृद्धि कर रहे हैं ।

एडहेसिव टेप की 250 से भी अधिक एसएसआई इकाइयों में हजारों कामगार लगे हुए हैं । पाटनरोधी शुल्क लागू करने से एडहेसिव टेप विनिर्माताओं को क्षति होगी ।

मै0 सांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

वर्तमान निर्यात बाजार बीओपीपी एडहैसिव टेप के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है । एडहैसिव टेप की निविष्ट लागत में किसी प्रकार की वृद्धि से वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धी बन जाएगा ।

भारतीय बाजार में बी ओ पी पी फिल्म का कोई पाटन नहीं हुआ है ।

घरेलू बी ओ पी पी फिल्म विनिर्माता अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं ।

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र(एचकेएसएआर)की सरकार, हांगकांग

प्रारंभिक जांच परिणामों के जवाब में, व्यापार और उद्योग विभाग, एचकेएसएआर की सरकार ने कहा है कि जांच अवधिक के दौरान एचकेएसएआर से भारत में हुए आयात की मात्रा उसके रिकार्डों में दर्शाई गई मात्रा से असामान्य रूप से अधिक थी । चूंकि प्राधिकारी ने केवल याचिका का अगोपनीय अंश ही उपलब्ध कराया है इसलिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रखा गया है जिससे वे आगे टिप्पणी न कर सकें ।

उनके रिकार्ड स्पष्ट करते हैं कि हांगकांग एक अलग सीमाशुल्क क्षेत्र होने के अलावा, उसका भारत को बीओपीपी फिल्मस का निर्यात बहुत कम मात्रा में हुआ था । पूरे विश्व से वस्तुओं को हांगकांग के मार्ग से स्वतंत्र रूप से लाया-ले जाया जा सकता है । तथापि मुक्त निर्यात को उनके अपने निर्यात से अलग नहीं किया जा सकता है । इसलिए पाटन के पर्याप्त साक्ष्य के बारे में आश्वस्त नहीं है ।

मै0 ओमान प्लास्टिक इंडस्ट्रीज आई आई सी

कम्पनी ने कहा है कि वे बी ओ पी पी फिल्म का विनिर्माण नहीं कर रहे हैं और न ही भारत को निर्यात कर रहे हैं ।

मै0 टोयो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

कंपनी ने कहा है कि पिछले पांच सालों में उसने भारत के साथ कोई व्यापार नहीं किया है।

मै0 पी टी त्रियास सैन्टोसा टीबीके, सिंगापुर

कम्पनी ने कहा है कि वे भारत सहित समूचे विश्व में बी ओ पी पी फिल्म और अन्य पैकेजिंग फ्लैक्सिबल फिल्म के निर्यातक हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में बी ओ पी पी फिल्म का कोई पाटन नहीं हो रहा है क्योंकि बी ओ पी पी फिल्म की आपूर्ति इस समय कम हो रही है। अतः निर्यातकों द्वारा पाटित कीमतों पर उत्पादों की बिक्री का कोई कारण नहीं है।

उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि प्रश्नावली को भरना एक समय खपाऊ काम है और उन्होंने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

मै0 पी टी इनामुती इंडीपैक, जकार्ता

कंपनी ने बताया है कि उन्होंने भारत को कभी भी बी ओ पी पी उत्पादों का निर्यात नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने घरेलू रूप से अथवा अंतर्राष्ट्रीय रूप से कभी भी बी ओ पी पी उत्पादों का उत्पादन अथवा उनकी बिक्री नहीं की है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

2. 5 घरेलू उद्योग के बारे में

निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह 'निर्धारित' करना अपेक्षित होता है कि याचिका घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर की गई है। तथापि, इस प्रकार के 'निर्धारण' को अन्तिम निर्धारण नहीं कहा जा सकता है।

नियमों के परन्तुक में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जांच उस स्थिति में शुरू की जा सकती है यदि याचिका का समर्थन करने वाले उत्पादकों का हिस्सा कुल

उत्पादन के 25% से अधिक बनता हो। इस प्रकार, इस नियम में यह बात स्पष्ट तौर पर निहित है कि मामला उस स्थिति में शुरू किया जा सकता है यदि याचिका का समर्थन करने वाले और याचिकाकर्ता कम्पनियों के रूप में जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 25% से अधिक बनता है। ऐसा मामला होने के कारण समूचे तर्क में कोई दम नहीं है।

2.6 जांच अवधि के बारे में

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में जांच की अवधि 18 माह (अप्रैल 1999-सितम्बर 00) की है। इस प्रकार प्राधिकारी के लिए पूर्ववर्ती अवधियों के संदर्भ में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करनी अपेक्षित है। यह उचित नहीं होगा कि अप्रैल-सितम्बर 00 की अवधि के आंकड़ों को वार्षिक रूप प्रदान किया जाए और तत्पश्चात् उनकी तुलना 1999-00 के की जाए क्योंकि 1999-00 स्वयं ही जांच अवधि का भाग है। चूंकि जांच की अवधि 18 मार्च की है इसलिए यह उचित होगा कि जांच अवधि के आंकड़ों को वार्षिक रूप प्रदान किया जाए और तत्पश्चात् उनकी तुलना पूर्ववर्ती वर्षों के साथ की जाए। विकल्पतः ऐसी तुलना मासिक औसत पर सभी आंकड़ों को कम करके की जा सकती है। तथापि, इससे भी स्थिति में खास परिवर्तन नहीं आएगा।

यद्यपि प्राधिकारी यह मानते हैं कि जांच अवधि की तुलना पूर्ववर्ती वर्षों के साथ करना नियमानुसार अपेक्षा है और यह प्राधिकारी की सुसंगत प्रक्रिया है।

इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि समूची तुलना तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के साथ करना उचित होगा। प्राधिकारी की प्रक्रिया किसी निश्चित अवधि में तुलना करने की रही है।

3.

याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और नियमों के संदर्भ में उठाए गए तर्कों और जो इस मामले पर प्रभाव डालते हैं, पर इस अधिसूचना में विचार किया गया है और उन पर उचित स्थानों पर कार्रवाई की गई है।

घ. प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्यों का खुलासा

4. प्रकटन विवरण के उत्तर में व्यक्त किए गए विचारों पर इन जांच परिणामों में उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक ये नियमानुसार संगत हैं और मामले पर प्रभाव डालते हैं।

ड. विनाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद ताइवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, यू.ए.ई, सिंगापुर तथा थाईलैंड व. मूल की अथवा वहां से निर्यातित बाइएक्सली ओरिएंटल पोली प्रोपीलीन फिल्म (बीओपीपी) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है। बाइएक्सली ओरिएंटल पोली प्रोपीलीन फिल्म (बीओपीपी) पोली प्रोपीलीन से निर्मित एक हाई परफॉरमेंस बाइएक्सली ओरिएंटल, स्पेशल फिल्म है। बी ओ पी पी फिल्म का उत्पादन भिन्न-भिन्न किस्मों और प्रकारों में किया जाता है जिनका इस्तेमाल व्यापक अन्तिम उपयोग संबंधी अनुप्रयोगों में किया जाता है। बी ओ पी पी फिल्म का उत्पादन, उत्पादन के भिन्न-भिन्न तरीकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें कई तकनीकी विशेषताओं से अलग किया जाता है जिनमें शामिल हैं - फिल्म की मोटाई और चौड़ाई, फिल्मों की फीडिंग प्रक्रिया और फार्मूला, उत्पादन, पर्यावरणिक स्थितियाँ एवं ऑन-लाइन कोटिंग अथवा सह-निष्कासन जैसी कुछ विशिष्ट क्षमताएं। मुख्यतः लाईन क्षमताओं के सम्मिश्रण पर निर्भर करते हुए बी ओ पी पी फिल्म कमोडिटी टाइप अथवा स्पेशलिटी टाइप को हो सकती है।

संबद्ध देशों के मूल के बाइएक्सली ओरिएंटेड पोली प्रोपीलीन फिल्म (बीओपीपी) को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क शीर्ष सं० 3920.20 तथा भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित वस्तु वर्णन एवं कोडिंग प्रणाली पर आधारित) की संख्या 3920.2000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान वर्गीकरण पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

प्राधिकारी नोट करते हैं वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद बाइएक्सली ओरिएंटेड पोलीप्रोपीलीन फिल्म है। ऐसी बीओपीपी फिल्म का उत्पादन पोलीप्रोपीलीन के निष्कर्षन द्वारा किया जाता है। इस बेस फिल्म का एक बार उत्पादन हो जाने के बाद इसके कुछ गुणधर्मों में वृद्धि करने के लिए इसे तत्पश्चात् आगे और प्रसंस्कृत (जैसे कि मेटेलाइजेशन) किया जा सकता है। तथापि उत्पाद की मूलभूत भौतिक, तकनीकी और रासायनिक विशेषताएं वही बनी रहती हैं और इसका इस्तेमाल पैकेजिंग में भी किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि बेस फिल्म के उत्पादन हेतु अपेक्षित निवेशों और ऐसी बेस फिल्म के धातुकरण से इस बात की पुष्टि होती है कि धातुकृत बीओपीपी फिल्म बीओपीपी फिल्मों का एक प्रकार है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहले पोलिस्टर फिल्मों के संबंध में जांच की गई थी।

प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि धातुकृत बीओपीपी फिल्मों को शामिल करके जाँच के क्षेत्र का विस्तार नहीं किया गया है। ऐसी बीओपीपी फिल्में याचिका में शामिल की गई थी। यहा तक की निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन की गणना और क्षति के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध की गई सूचना में भी धातुकृत फिल्में शामिल थी। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि बीओपीपी फिल्में और साधारण फिल्में समान सीमाशुल्क वर्गीकरण में आती है तथा आयात एवं निर्यात कीमत के बारे में सूचना डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा संकलित आंकड़ों पर आधारित थी।

जहाँ तक सीबीईसी के परिपत्रों और माननीय उच्चतम न्यायालय का संबंध है, यह माना जाता है कि धातुकृत साधारण फिल्म का उत्पादन सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क के अर्थ के भीतर आता है। तथापि वर्तमान के प्रयोजन से "उद्योग" के निर्धारण का उद्देश्य कुल मिलाकर उस उद्देश्य से भिन्न है जिसके

लिए उत्पादन को सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क के भीतर माना जाता है। सीमाशुल्क अथवा उत्पाद शुल्क के प्रयोजनार्थ उत्पादन और पाटनरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ उत्पादन को समान माना जा सकता है।

उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान जाँच के क्षेत्र में धातुकृत बीओपीपी फिल्मों समेत सभी प्रकार की बीओपीपी फिल्में आती हैं।

घ. समान वस्तुएँ

6. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि 'समान वस्तु' का तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु से है जो जाँचाधीन उत्पाद से हर प्रकार से समान अथवा समनुरूप है अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में ऐसी दूसरी वस्तु से है जिसकी विशेषताएँ जाँचाधीन वस्तुओं की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती जुलती हैं।

पैरामें दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर प्राधिकारी समान वस्तु के बारे में प्रारंभिक जाँच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

छ. घरेलू उद्योग

7.1 पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार 'घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में अथवा उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे हुए हैं अथवा ऐसे निर्यातकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है परन्तु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं जो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का अंग नहीं माना जाएगा।'

7.2 ऊपर दी गई घरेलू उद्योग की परिभाषा को नियमावली के नियम 5 द्वारा और स्पष्ट किया गया है जो निम्नलिखित है:-

'.....आवेदन को उस स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया माना जाएगा यदि उसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया जिनका सामूहिक उत्पादन उक्त आवेदन का समर्थन अथवा उसका विरोध, जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50% से अधिक बनता हो।'

7.3 यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से बीओपीपी फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्त्ताओं के साथ-साथ समर्थकों का कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है और इसलिए उनके पास उपरोक्त नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का आधार है।

	जाँच अवधि के दौरान उत्पादन	% हिस्सा
समर्थकों के साथ याचिका (एसोसिएशन के सदस्य)	54161	92
अन्य (गैर-सदस्य)	4695	8
कुल भारतीय उत्पाद	58856	100

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मामले में याचिका एसोसिएशन आफ बीओपीपी प्रोड्यूसर्स द्वारा दायर की गई थी। याचिका का किसी ने विरोध नहीं किया है। जाँच की शुरुआत के समय भागीदार कम्पनियों का उत्पादन पात्र भारतीय उत्पादन के 25% से अधिक बनता था। इसके अलावा याचिकाकर्त्ताओं के साथ-साथ समर्थकों का उत्पादन पात्र भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक बनता था। इस प्रकार इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि याचिका में जाँच की शुरुआत के समय आधार की पुष्टि नहीं होती थी। जाँच की शुरुआत के बाद मैक्स एण्ड सुप्रीम द्वारा याचिका का विशिष्ट रूप से समर्थन किया गया है। इस प्रकार याचिका आधार संबंधी अपेक्षा को पूरा करती है।

ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन: पाटन मार्जिन - सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना ।

(क) तुलना संबंधी नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथा संभव उसी समयावधि के दौरान की गयी बिक्रियों के संबंध में की जाएगी । जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी । उक्त अंतर में शामिल है बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, वास्तविक विशेषताएं तथा अन्य ऐसे अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं ।"

(ख) पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचारों पर ऊपर पैरा-2 में कार्रवाई की गई है और उन्हें संक्षिप्तता की वजह से यहां दोहराया नहीं गया है ।

(ग) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 में यथा निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को शामिल करने वाले प्रावधानों तथा इस संबंध में अपनायी जा रही पद्धति का अनुपालन किया है । उपरोक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन निकाला है ।

8.0 सामान्य मूल्य

8.1 मै0 अल खलीज पोलिप्रोपीलीन प्रोडक्ट्स कम्पनी साओग, ओमान सल्तनत:

(i) मै0 अल खलीज ने प्रारंभिक जॉच परिणामों के बाद जॉच में उत्तर दिया है ।

(ii) बीओपीपी फिल्म एक प्रसंस्करण उद्योग है और इसमें व्यापक गुणवत्ता के उत्पाद तैयार होते हैं । फिल्म रोलों का श्रेणीकरण ए ग्रेड (प्राथमिक/प्रथम), बी ग्रेड (द्वितीय) अथवा पुनः प्रसंस्करण योग्य के रूप में किया जाता है । विश्व के सभी उत्पादक प्राथमिक गुणवत्ता के अलावा बी ग्रेड की फिल्मों

- की बिक्री करते हैं। भारत अत्यधिक लागत संवेदी बाजार है और भारत के उपयोक्ता 'बी' ग्रेड की फिल्म चाहते हैं।
- (iii) 'बी' ग्रेड की फिल्मों की बिक्री 'ए' ग्रेड की फिल्मों से लगभग 40-50% सस्ती कीमत पर की जाती है। बी ग्रेड की फिल्म की कीमत की तुलना 'बी' ग्रेड की कीमत के साथ की जानी चाहिए और न कि 'ए' ग्रेड की कीमत के साथ।
- (iv) उन्होंने उल्लेख किया है कि भारतीय बीओपीपी उद्योग को आयात शुल्क के रूप में पहले से ही पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है।
- (v) उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत में औसत बिक्री कीमत की तुलना में घरेलू कीमतें अल्प निष्पादन अवधि, समय पर डिलीवरी एवं छोटे लाट तथा खुले भुगतान की शर्तों जिनमें उच्च जोखिम होता है, जैसे कारणों की वजह से अपेक्षाकृत अधिक है।
- (vi) उन्होंने यह भी बताया है कि वे ग्रेडवार खाते और लागत संबंधी आंकड़े नहीं रखते हैं। अतः सभी ग्रेडों की सम्मिलित सूचना प्रस्तुत की गई है।
- (vii) यद्यपि निर्यातक ने सौदेवार विवरणों में विनिर्देशनों का उल्लेख किया है लेकिन उन्हें अपने उत्तर में कही भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

निर्यातक द्वारा दायर उत्तर का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। बिक्री कीमत ढांचा संबंधी विवरण के अनुसार घरेलू बाजार में सौदेवार विवरण के आधार पर औसत बिक्री कीमत *** आरओ प्रति मी० टन बैठती है। कम्पनी ने *** आर ओ प्रति मी० टन की उत्पादन लागत का दावा किया है। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:-

(क) घरेलू बाजार में प्रत्येक सौदे के लिए कारखानागत बिक्री कीमत का निर्धारण किया गया है। ऐसी बिक्री कीमत की तुलना कम्पनी द्वारा दावा की गई कारखानागत उत्पादन लागत के साथ की गई है।

(ख) इस विश्लेषण से यह पता चलता है कि निर्यातक को अपनी घरेलू बिक्रियों के 30% के संबंध में घाटा हुआ है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के तहत पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा-2 (i)

मे यह प्रावधान है कि जब प्रतियूनिट लागत से कम बिक्री की मात्रा विचाराधीन सौदे की मात्रा के 20% से कम बनती हो तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण में उक्त बिक्रियों की अनदेखी कर सकते हैं।

(ग) प्राधिकारी घाटे वाली बिक्रियों को नजरअंदाज करते हुए लाभदायी घरेलू बिक्रियों के लिए निर्यात के संबंध में कारखानागत स्तर पर भारित औसत बिक्री मूल्य के अनुसार सामान्य कीमत..... अमरीकी डालर किग्रा 0 टन निर्धारित करते हैं।

8.2 संबद्ध देशों के अन्य निर्यातक:-

संबद्ध देशों के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों में से किसी ने भी प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में एवं तरीके से उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विचार करते हुए उत्पादन की प्रतिकूलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण अमरीकी डालर *** किग्रा 0 टन करते हैं।

8.3 निर्यात कीमत

मै 0 अल खलीज पोलीप्रोपोलीन प्रोडक्ट्स कम्पनी सेओग, ओमन सल्तनत

निर्यातकों में से एक निर्यातक मै 0 अल खलीज पोलीप्रोपोलीन प्रोडक्ट्स कम्पनी सेओग, ओमन सल्तनत ने निर्यात कीमत के निर्धारण से संबद्ध सूचना प्रस्तुत की है। निर्यातक ने जाँच अवधि के दौरान ए तथा बी ग्रेड दोनों प्रकार की फिल्मों का भारत को किए गए निर्यातों का ब्यौरा मुहैया कराया है। यद्यपि अधिकांश बिक्रियाँ बी ग्रेड फिल्मों की हुई है। तथापि निर्यातक ने भारत को बी ग्रेड बीओपीपी फिल्मों की बिक्री को छोड़कर ए ग्रेड की फिल्मों की बिक्री के आधार पर निर्यात मूल्य का दावा किया है। निर्यातक ने ऐसे वर्गीकरण तथा उनके आवर्जन का कोई कारण अथवा औचित्य इंगित नहीं किया है। निर्यातक ने यह भी स्वीकार किया है कि वे ग्रेड बार कोई लेखा तथा लागत संबंधी आंकड़े नहीं रखते हैं। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, निर्यात मूल्य पर पहुँच के लिए भारत को किए गए सभी निर्यातों पर विचार करने का प्रस्ताव है। निर्यातक द्वारा समुद्री भाड़े तथा समुद्री बीमा इत्यादि के लिए किए गए समायोजनों के दावों पर विचार किया गया है। प्राधिकारी निर्यात मूल्य..... अमरीकी डालर किग्रा 0 टन निर्धारित करते हैं।

8.4 संबद्ध देशों के अन्य निर्यातक

संबद्ध देशों के सभी अन्य निर्यातकों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी डीजीसीआई एंड एस कलकत्ता द्वारा संकलित सूचना के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कारखानागत निर्यात कीमत निकालने का प्रस्ताव करते हैं। कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़े, लदान प्रभारों, समुद्री बीमा, कमीशन इत्यादि के संबंध में समायोजन का दावा किया है।

8.5 प्राधिकारी का मानना है कि निर्यातक मै0 अलखली ने दोनों ग्रेडों को अलग-अलग मानने की बात को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, निर्यातक यह स्वीकार करता है कि वह दोनों ग्रेडों के लिए अलग-अलग रिकार्ड नहीं रखता है। दोनों ग्रेडों की सूचना का एक साथ जोड़ना उचित है।

8.6 पाटन मार्जिन

प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में यथा निर्धारित सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों को अपनाने की सुसंगत रणनीति का अनुपालन करने का प्रस्ताव करते हैं।

संबद्ध देश	निर्यातक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत अम0 डालर में	पाटन मार्जिन किग्रा0	निर्यात कीमत के % के रूप में पाटन मार्जिन
ताईवान	सभी निर्यातक	***	***	***	73.68
हांगकांग	सभी निर्यातक	***	***	***	61.77
इंडोनेशिया	सभी निर्यातक	***	***	***	72.57
ओमान	मै0 अल खलीज अन्य निर्यातक	***	***	***	28.77

सिंगापुर	सभी निर्यातक	***	***	***	47.86
थाइलैंड	सभी निर्यातक	***	***	***	81.48
यूएई	न्यूनतम आयात	***	***	***	88.54

अ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9.0 प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण में क्षति से संबंधित सभी संकेतकों को ध्यान में रखा है। इसमें पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के तहत विनिर्दिष्ट क्षति के निर्धारण हेतु सिद्धांतों में यथा निर्धारित सभी संगत मापदंडों की जाँच शामिल थी। प्राधिकारी ने (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की जाँच की है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय स्तर तक कम करना था अथवा कीमत वृद्धि को रोकना था जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच घरेलू उद्योग के बिक्री (वास्तविक अथवा संभावित), उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, उत्पादकता, स्टॉक, बिक्री कीमत, लाभप्रदता, निवेश पर आय में कमी, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह (वास्तविक और संभावित), रोजगार, मजदूरी, विकास, धन जुटाने की क्षमता जैसे मापदंडों पर विचार करके की गई है। क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की विस्तृत जाँच की है। क्षतिरहित कीमत की जाँच करते समय प्राधिकारी ने जाँच अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के उपयोग एवं उपयोगिता घरेलू उद्योग द्वारा किए गए व्यय जैसे संगत कारकों का समुचित विश्लेषण किया है।

प्रारंभिक जाँच परिणामों के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग को क्षति दो याचिकाकर्ता कम्पनियों अर्थात् फ्लैक्स एवं गुजरात प्रोपैक पर आधारित थी। तथापि मै0 सुप्रीम और मैक्स ने प्रारंभिक जाँच परिणाम के बाद लागत एवं क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध की है। प्राधिकारी ने क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस सूचना को शामिल करना उचित समझा है। तदनुसार क्षति संबंधी ये जाँच परिणाम चार कम्पनियों पर आधारित हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मै0 मैक्स और मै0 सुप्रीम द्वारा क्षति एवं लागत संबंधी सूचना मौखिक सुनवाई के बाद उपलब्ध की है और उसका अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल में रखा गया था ।

9.1 निवेश एवं क्षमता उपयोग: घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण भागीदार तथा समर्थक कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी पर उचित आय को ध्यान में रखकर किया गया है । क्षति मार्जिन की गणना के लिए, घरेलू उद्योग कि भारत औरसत कारखानागत क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध वस्तु के पहुँच मूल्य के साथ की गई है ।

9.2 आयातों की मात्रा

यूआई को छोड़कर संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यूआई से हुए आयातों की मात्रा 2.6% है जोकि 3% के न्यूनतम स्तर से कम है । जाँच अवधि के दौरान यूआई से हुए आयातों मात्रा न्यूनतम है और इसलिए प्राधिकारी यूआई से हुए आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उचित नहीं समझते । इन परिस्थितियों में यूआई को इस पाटनरोधी जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है और प्रारंभिक जाँच परिणामों की पुष्टि की जाती है ।

9.3 आयातों की मात्रा तथा बाजार हिस्सा

किग्रा0 में

देश	1997-98	1998-99	1999-00	4/00 से 9/00	जाँच अवधि	जाँच अवधि वार्षिक
संबद्ध देश	205472	637974	1775323	275725	20512048	1367365
अन्य देश	846445	1411910	1490639	632384	2123023	1415349
देश का कुल	1051917	2049884	3265962	908109	4174071	2782714

आयात						
भारतीय उत्पादको की बिक्री	3524800 0	3997300 0	3934100 0	21991000	61332000	4088800 0
देश में माँग	3629991 7	4202288 4	4260697 2	22899109	65506071	4367071 4
कुल आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा (%)	19.5%	31.1%	54.4%	30.4%	49.1%	49.1%
माँग में बाजार हिस्सा						
संबद्ध देश	0.6%	1.5%	4.2%	1.2%	3.1%	3.1%
अन्य देश	2.3%	3.4%	3.5%	2.8%	3.2%	3.2%
भारतीय उद्योग	97.1%	95.1%	92.3%	96.0%	93.6%	93.6%
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

जैसाकि उपरोक्त से देखा जाता है, वर्ष 1997-98 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान (वार्षिक) संबद्ध देशों (अर्थात् यूएई को छोड़कर) से हुए आयातों की मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। प्रतिशत के रूप में भी उक्त मात्रा 1997-98 में 19.5% से बढ़ाकर 49.1% हो गई है। संबद्ध देशों की माँग में बाजार हिस्सा जो 1997-98 में 0.6 प्रतिशत था वह जाँच अवधि के दौरान बढ़कर 3.1 % हो गया है और घरेलू उद्योग का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 97.1 प्रतिशत से घटकर 93.6 प्रतिशत हो गया है।

9.4 उत्पादन

इस अवधि के दौरान भागीदार कम्पनियों और समर्थक कम्पनियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादन में हुई वृद्धि को मै0 फ्लैक्स इंडस्ट्रीज द्वारा वाणिज्य उत्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत एवं बिक्री प्राप्ति के साथ देखना होगा। यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथापि उद्योग उस कीमत पर अपने उत्पाद की बिक्री करने में समर्थ नहीं हुआ है जिस कीमत पर उसे उत्पादन की पूरी लागत भी प्राप्त हो सके। अतः उत्पादन में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप उसके घाटे में वृद्धि हुई है।

9.5 क्षमता उपयोग: घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है जैसाकि पूर्ववर्ती पैरा में उल्लेख किया गया है यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथापि उद्योग उस कीमत पर अपने उत्पादन की बिक्री करने में समर्थ नहीं हुआ है जिस कीमत पर उसे उत्पादन की पूरी लागत भी प्राप्त हो सकें।

9.6 बिक्री

इस अवधि में भागीदार/समर्थक इकाईयों की बिक्री में वृद्धि हुई है। इसके अलावा उत्पादन एवं बिक्री की मात्रा का सीधा सम्बन्ध उत्पादन लागत एवं बिक्री प्राप्ति से है। संबद्ध देशों से निर्यात की कीमत कम हुई है जिसके परिणामस्वरूप पहुँच मूल्य में कमी आई है जिसके कारण बिक्री प्राप्ति उचित स्तर तक नहीं पहुँच सकी है।

9.7 आयातों की पहुँच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत

पिछले वर्षों के दौरान पहुँच कीमत में कमी आ रही है। पिछले वर्षों के दौरान बिक्री कीमत में भी कमी आ रही है जो संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत में हुए परिवर्तन के अनुरूप नहीं है। संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत एवं पहुँच कीमत की तुलना से यह नोट किया जाता है कि भागीदार कम्पनियों ने 1999-2000 में कीमतों में वृद्धि की थी जो उत्पादन लागत में तेजी से हुई वृद्धि का परिणाम थी। तथापि, उत्पादन लागत

में हुई उक्त वृद्धि जाँच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से अधिक थी। संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में हमारी कटौती हो रही है।

9.8 रोजगार

भागीदार समर्थक कम्पनियों के रोजगार स्तर में खराब संचालन स्तर की वजह से कोई खास परिवर्तन नहीं आया है।

प्राधिकारी की जाँच-घरेलू उद्योग को क्षति

9.9 इस तर्क के मद्देनजर कि भागीदार कम्पनियों का उत्पादन पात्र भारतीय उत्पादन के 50 % से कम बनता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कहने का कोई कानूनी आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग की क्षति की जाँच उन उत्पादकों के संबंध में की जानी चाहिए जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक बनता है।

9.10 प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि केवल इस वजह से एसोसिएशन ने वर्तमान याचिका दायर की है यह अर्थ नहीं निकलता है कि प्राधिकारी उक्त एसोसिएशन के सभी सदस्यों के संबंध में दी गई सूचना पर विचार करने के लिए बाध्य हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि भागीदार कम्पनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 25% से ज्यादा बनता है। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति के निर्णय के पश्चात एसोसिएशन द्वारा दिए गए समर्थन का अर्थ निकलता है कि एसोसिएशन के सदस्य याचिका का समर्थन कर रहे हैं। इसप्रकार प्राधिकारी यह मानते हैं कि समर्थकों के साथ-साथ भागीदार कम्पनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक बनता है।

मैक्स और सुप्रीम ने प्रारंभिक जाँच परिणामों के पश्चात क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी ने इस सूचना को भी क्षति के निर्धारण में शामिल किया है। इस प्रकार वर्तमान जाँच परिणाम में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण उन उत्पादकों के लिए किया गया है जिनका उत्पादन पात्र भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक बनता है।

9.11 निष्कर्ष

निम्नलिखित मानदण्डों से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है:-

- ❖ संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग उस स्थिति में नहीं था कि वह अपनी बिक्री कीमत को उचित स्तर तक बढ़ा सके;
- ❖ संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं का बाजार हिस्सा बढ़ा है;
- ❖ भारतीय बाजार में निर्यातक द्वारा निर्यात कीमत में की गई कमी के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप संबद्ध देशों से पहुँच मूल्य में गिरावट आई है ;
- ❖ संबद्ध देशों से पाटित आयतों के कारण भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग का कीमतों में भारी कटौती हो रही है;
- ❖ घरेलू उद्योग को बिक्री कीमतों को इष्टतम स्तर तक बढ़ाने में कठिनाई हो रही है ।
- ❖ घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य किया गया है । घरेलू उद्योग को हुई भारी वित्तीय हानि इसका प्रत्यक्ष परिणाम है ;
- ❖ जांच अवधि के दौरान यूएई से हुए आयातों की मात्रा न्यूनतम है ।

उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति यूएई को छोड़कर संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है ।

अ. कारणात्मक संबंध

- 10.1 संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं । अन्य देशों से आयात काफी उच्च कीमतों पर हुई हैं या इसकी मात्रा न्यूनतम से कम रही है । इसलिए, अन्य देशों से हुए आयातों से भारतीय उद्योग को कोई क्षति नहीं हा रही है ।
- 10.2 भारत में बीओपीपी फिल् की मांग कमोबेश स्थिर रहती है । घरेलू उद्योग के पास भारत में बीओपीपी फिल्म की समूची मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता है । इसलिए, मांग में आए परिवर्तनों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

10.3 याचिकाकर्ताओं ने दोहराया है कि भारत में बीओपीपी फिल्म उद्योग इतना पुराना नहीं है जिसे प्रौद्योगिकी विकास के कारण कोई क्षति पहुँच सकती है। उद्योग ने नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है और इसे अद्यतन बनाने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। वस्तुतः भारत विकसित देशों को बीओपीपी फिल्म का निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश है जहाँ उत्पादन सुविधाएँ भी मौजूद हैं।

11.0 कीमत संबंधी वचन पत्र

11.1 कीमत वचन पत्र से संबंधित जांच के स्थगन अथवा समापन से संबंधित नियम 15 में यह व्यवस्था है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में किसी जांच को स्थगित अथवा समाप्त कर सकता है यदि संदर्भाधीन वस्तु का निर्यातक निर्दिष्ट प्राधिकारी को कीमतों में संशोधन करने के बारे में वचनपत्र प्रस्तुत करता है ताकि पाटित कीमतों पर भारत में उक्त वस्तु का कोई निर्यात न किया जा सके अथवा विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में कीमतों में संशोधन हेतु वचनपत्र देता है ताकि पाटन का क्षतिकारी प्रभाव समाप्त हो सके और निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि पाटन का क्षतिकारी प्रभाव समाप्त हो गया है।

11.2 यद्यपि एक निर्यातक अर्थात् मै0 अलखलिज ने कीमत वचनपत्र देने के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की है तथापि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने न तो मुद्दे पर चर्चा हेतु निर्धारित की गई बैठक में भाग लिया और न ही उसने लिखित में कोई वचनपत्र प्रस्तुत किया। प्राधिकारी यह मानते हैं कि कीमत वचनपत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। निर्यातकों से एक निर्यातक ओमान के सल्तनत (अल खनिज) मै0 अल खनिज पोलिप्रोपॉलिन प्रोडक्ट्स कम्पनी एसएओजी, ने कीमत संबंधी वचनपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। प्रस्ताव की विस्तृत जाँच की गई थी और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाया कि निर्यातक द्वारा प्रस्तावित वचनपत्र को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि इससे सपाटन के क्षतिकरण प्रभाव

को समाप्त होता है। निर्यातक ने ऐसी सभी उचित सूचना मुहैया कराने पर सहमति व्यक्त की है, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी संगत और जरूरी मानते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्यातक के कीमत संबंधी वचनपत्र को स्वीकार किया है और तदनुसार इस कम्पनी से सभी प्रकार के बीओपीपी फिल्मों के निर्यातों के मामले में कोई शुल्क नहीं लगेगा। तथापि निर्यातक द्वारा इस वचनपत्र के

निष्पादन में किए जाने वाले किसी उल्लंघन के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में विशिष्ट शिफारिशों के लंबत रहने तक, प्रारंभिक निष्कर्षों में यथानिर्धारित शुल्क अनन्तिम रूप से लगा होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस वचनपत्र को केवल इस कम्पनी द्वारा भारत को सीधे किए गए निर्यातों के मामले में लागू किया जाएगा। यदि वस्तुओं का निर्यात किसी अन्य कम्पनी द्वारा किया जाता है तो नीचे यथा उल्लेखित अवशिष्ट शुल्क लागू होगा चाहे वे इस कम्पनी के उत्पाद ही क्यों न हों।

11.3 कम्पनी के उनके द्वारा निर्यातित बीओपीपी फिल्म के सभी रूपों के लिए अपने एक कीमत संबंधी वचनपत्र प्रस्तुत किया है। इस वचनपत्र में बीओपीपी फिल्म का 1.63 अमरीकी डालर प्रति किग्रा० की राशि होगी। वचनपत्र संबंधी कीमत आयातों के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य है।

ट. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

- 12.1** पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः ऐसे पाटन को समाप्त करना, जिससे याचिकाकर्ता कम्पनियों को क्षति पहुँच रही है और भारतीय बाजार में एक खुली और उच्च प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल करना है, जो देश के सामान्य हित में है।
- 12.2** यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से सम्बद्ध वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में पाटनरोधी उपायों से उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी विशेषतः यदि पाटनरोधी शुल्क को ऐसी राशि तक सीमित रखा जाए जो कि याचिकाकर्ता कम्पनी की क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, याचिकाकर्ता कम्पनियों का ह्रास रुकेंगे और सम्बद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से सम्बद्ध देशों से होने वाले आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई अक्षर नहीं पड़ता।
- 12.3** याचिकाकर्ता कम्पनियों को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कम्पनियों के लिए क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर

पर उत्पादन की अधिकतम लागत पर विचार करके भारत में याचिकाकर्ता कम्पनियों और समर्थक कम्पनियों के लिए बीओपीपी फिल्म की क्षति रहित बिक्री कीमत पर भरोसा किया है।

(ड). निष्कर्ष

13.0 पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- (क) सम्बद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित बीओपीपी फिल्म का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके कारण पाटन हुआ है।
- (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- (ग) घरेलू उद्योग को उक्त क्षति सम्बद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन द्वारा हुई है।

14.0 पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- (क) प्राधिकारी ताइवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, सिंगापुर, और थाइलैंड के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-39 के अंतर्गत आने वाली बीओपीपी फिल्म के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
- (ख) प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने पर विचार किया जिसे वसूल किया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। इस प्रयोजनार्थ जाँचों की औसत पहुँच कीमत की तुलना जाँच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कम्पनियों की क्षति रहित बिक्री कीमत के साथ की गई थी। जहाँ अंतर पाटन मार्जिन से कम रहा था वहाँ पाटन मार्जिन से कम शुल्क की सिफारिश की जाती है।

- (ग) तदनुसार, प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने के बारे में प्रारंभिक जाँच परिणामों की पुष्टि करते हैं और सम्बद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाली बीओपीपी फिल्म के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं तथापि, मै0 अलखलीज से हुए निर्यातों के मामले में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा जिसमें

प्राधिकारी ने कम्पनी द्वारा दिए गए कीमत वचनपत्र को स्वीकार किया है । पाटनरोधी शुल्क नीचे कॉलम(4) में उल्लिखित राशि होगी:-

क्र.सं.	संबद्ध देश	निर्यातक का नाम	अम0 डालर प्रति किग्रा. में पाटनरोधी शुल्क की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ताइवान	सभी निर्यातक	८.१८
2	हांगकांग	सभी निर्यातक	८.८३
3	इंडोनेशिया	सभी निर्यातक	८.५२
4	ओमान	मै0 अल खलीज अन्य निर्यातक	कोई शुल्क नहीं-कीमत वचनपत्र में उल्लिखित ८.५१
5	सिंगापुर	सभी निर्यातक	८.८०
6	थाईलैंड	सभी निर्यातक	८.१९

15. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 अथवा 9क के तहत लगा गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा ।
16. उपरोक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी 14.8.2001 के प्रारंभिक जाँच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।
17. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

एल. वी. सप्तश्रृंगि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th June, 2002

Final Findings

Subject : Anti-Dumping Investigations concerning imports of Biaxially Oriented Poly Propylene Film (BOPP) originating in or exported from Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Oman, UAE, Singapore and Thailand—Final Findings.

21/1/2001-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:
 - (i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified Initiation vide Notification No. 21/1/2001-DGAD dated the 30th May, 2001 with regard to Anti-Dumping Investigations concerning imports of Biaxially Oriented Poly Propylene Film (BOPP) originating in or exported from Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Oman, UAE, Singapore and Thailand and requested the interested parties to provide information and make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
 - (ii) The Authority notified preliminary findings vide Notification No. 21/1/2001-DGAD dated the 14th August, 2001 with regard to Anti-Dumping Investigations concerning imports of Biaxially Oriented Poly Propylene Film (BOPP) originating in or exported from Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Oman, UAE, Singapore and Thailand and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
 - (iii) The Authority forwarded a copy of the Preliminary Findings to known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the Preliminary Findings within forty days of the date of the letter;

- (iv) The Authority also forwarded a copy of the Preliminary Findings to the Embassies of Indonesia, Oman, UAE, Singapore, Thailand in New Delhi, Taipei Economic and Cultural Center, New Delhi and Hongkong Special Administrative Region, HK; with a request to furnish their views on the Preliminary Findings;
- (v) The Authority held a public hearing on 21st November, 2001 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the Domestic Industry, Exporters and Importers. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. Designated Authority in this finding has considered the written submissions thus received from interested parties;
- (vi) The Authority made the public file available to all interested parties containing non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties, for inspection, upon request;
- (vii) Arguments raised by interested parties before announcing of Preliminary Findings, which have been brought out in the Preliminary Findings notified earlier have not been repeated herein for sake of brevity. However, arguments raised by the interested parties have been appropriately dealt with in the Preliminary Findings and/or these findings;
- (viii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;
- (ix) Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 1999 to 30th September, 2000;
- (x) The Authority heard and discussed with the concerned interested parties the issues and submissions pertaining to price undertaking;
- (xi) The Authority received injury and costing information from two domestic producers, viz. M/s. Max India and Supreme Oriented. Further, questionnaire information was received from M/s. Al Khaleej, Oman. The Authority has accepted both the information, even though the same was after the preliminary findings. Issues raised by the exporter have been brought out in these findings. Further, the domestic producers have provided injury and costing information.
- (xii) *** in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules.
- (xiii) Central Government vide OM No.354/155/2001-TRU dated 17.6.2002 granted extension for a period of one month from 30.5.2002 for completion of this anti dumping investigation.

B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY:

2. The petitioner, exporters and importers have expressed their views and the same are briefly mentioned below:-

2.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY:

(a) ON PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

They have stated that they support the disclosure statement that BOPP films of all types are within the scope of the present investigations. Metalised BOPP Film and other BOPP Film are one like product. In support of it they have referred to the findings of European Commission on similar product viz. Polyester film. The Domestic Industry has stated that there is no justification for excluding metalised BOPP film or separate comparison of these films and base films for the following reasons as explained by the European Commission in their findings:

- (i) The materialization process consists of addition of metal, such as aluminum, and the same does not alter the basic physical, technical and chemical characteristics of polyester film.
- (ii) The fact that an additional production step is required for production of metalised polyester film (and the same results in higher cost of production and sales price) is not an element which could justify per se exclusion of certain type from the scope of the proceedings.
- (iii) The companies doing metalizing alone do not produce base polyester film and the same is purchased from different sources. The purchased polyester film is then metalized by these metalizers. This additional processing step undertaken by them is however, not sufficient in itself to justify their consideration as community producers of polyester film.
- (iv) Mere processing of the base polyester film (Metalization) does not alter the basic physical, technical and chemical characteristics of the product.

(b) ON STANDING OF DOMESTIC INDUSTRY

With regard to determination of standing, they have submitted that even at the time of initiation, the petitioners satisfied the standing to file the present petition. The petition has been filed by the Association.

The following producers are the members of the Association. M/s. Flex Industries Ltd, Gujarat propeck, Cosmo Films Ltd., Xpro India Ltd., Max India Ltd., Supreme Oriented.

The following producers of BOPP Films are not member of the Association, M/s. M.M. Rubber, M/s. Kabra Plastics, MPUPUL. Also

they have indicated that M/s. Kabra Plastics is an importer (or related to importer) of the subject goods.

The Executive Committee of the Association earlier decided to file a petition before the Designated Authority requesting imposition of appropriate anti-dumping duties on imports of BOPP Films. The decision was taken in accordance with the byelaws of the Association. Thus, the petition was filed by BOPP Producers Association and is specifically supported by Flex Industries Ltd., Gujarat Propack Ltd., Max India Ltd. and Supreme Oriented Films Ltd., The participating companies with the support of the supporting companies constituted more than 50% of eligible Indian Production even at the time of initiation.

Further they have stated that the proposition advanced by the exporter would imply that "the Designated Authority should first investigate and then initiate the investigations". However, they contend that the initiation is for investigation.

(c) ON PERIOD OF INVESTIGATION

The whole argument with regard to the investigation period advanced by the exporters deserves to be ignored. Followings are relevant in this regard:-

There is no requirement of passing a decision on the investigation period by the Designated Authority envisaged under the Rules. Neither the Application Proforma prescribes for the same – Rule 5(2), nor the principles governing investigations—Rule 6 nor requirements for preliminary findings – Rule 12 states so. Such being the case, the entire argument is misplaced and unsupported with law.

While financial year, accounting year and business cycle may be considered for determination of investigation period, it is submitted that there is no basis to argue that these are vital and relevant for determination of investigation period. It has been lost sight of that the accounting year of different companies even in India may be different (for instance, the present investigation itself, wherein the two participating companies had different accounting years) leave aside the exporters in the subject countries.

Administrative convenience can not overlook the core issue of "dumping and injury". "Dumping causing injury to the domestic industry" and not administrative convenience would decide the investigation period. It is like arguing that the administrative convenience of the hospital (and not illness of the patient) would decide whether and when the patient should be operated upon.

(d) ON DUMPING:

In the present investigation, only one exporter has responded. The exporter has responded after the preliminary findings. The domestic industry is greatly concerned about acceptance of such late response, which is jeopardizing the interests of the domestic industry as well as is a bonus for the exporters. Reliance is being placed upon the practices of European Union and USA in this regard, wherein no response from an exporter is admitted after the preliminary finding.

Petitioners reiterate that the response filed by the exporter can not be admitted for the following further reasons:

1. The response is unaccompanied with a meaningful non-confidential summary.
2. The non-confidential summary of information relating to Appendix-1 (relating to home market sales), Appendix-2 (exports to India), and cost of production are not provided on indexed basis. Even information such as certificate of correctness is provided on confidential basis. Hence, the whole response deserves to be rejected in accordance with the practice of other investigating Authorities world over.
3. The domestic industry is greatly concerned over the attitude of the exporter in cooperating with the Designated Authority, This is a situation of selective cooperation by the exporter.
4. Notwithstanding above, they have submitted as under with regard to the assessment of dumping margin proposed to be made by the Designated Authority.
 - (i) Grading of the product as prime/first/second/ is merely a classification of the product after production. Cost of production of all these types remains the same. While reprocessible production is required to be simply ignored and only net saleable production is required to be considered, we submit that the exporter seems to have determined its cost of production, considering reprocessible production. Should it be the case, it is submitted that the cost of production is required to be determined on the basis of net saleable production.
 - (ii) Unless the exporter has sold the material as "seconds/B Grade" and the same is evident from the invoice, the claim is unsustainable.
 - (iii) Should the selling price of seconds be compared with cost of production, it would imply that such sales were below cost of production (such seconds are normally sold at prices significantly lower than prices of prime product). Such being the case, normal value in such cases would get determined based on cost of

production + reasonable profits. It would thus appear that there is dumping of both the types.

- (iv) Should sufficient documentary evidence not exist to prove that the exporter has sold different grades in both the markets, it would imply that the export price and normal values are required to be assessed on average basis cumulatively for both the grades.

(e) ON INJURY:

With regard to injury to the domestic industry, they reiterate their submissions made earlier in this regard. We have already provided sufficient information, which shows that the domestic industry has suffered material injury from the dumped imports from subject countries. The same is also acknowledged in the disclosure statement. They submit that the following parameters show injury to the domestic industry due to dumped imports:-

Market share of imports from subject countries has increased in absolute terms as also in relation to imports and consumption in India.

Though production, sales and capacity utilization of the domestic industry increased, domestic industry suffered financial losses per unit of the product, in spite of significant reduction in the incidence of overhead costs.

The industry made its best efforts to sell its produce. However, the industry was not able to recover its cost of production, leave alone profit.

Export price from the subject countries steeply declined. This directly resulted in decline in the landed price of imports. The decline in the export price was in spite of appreciation of Indian Rupee.

Landed price of imports from subject countries was significantly below the selling price of the domestic industry causing severe price undercutting in the Indian market. In fact, the imports were earlier not undercutting the prices of the domestic industry. However, imports started undercutting the domestic industry from 1999-2000, which intensified in the investigation period. This prevented the domestic industry from recovering their cost of production.

All the parameters, collectively and cumulatively show that domestic industry suffered material injury from the dumped imports from subject countries.

(f) **DUTY ON FIXED AMOUNT BASIS**

It is submitted that the cost of production of the subject varies significantly with the changing raw materials prices. Further, the raw material prices also keep changing considering the prices of other petrochemical products. In view of the same, it is requested that the anti dumping duty may kindly be recommended in terms of fixed amounts, expressed in US \$.

2.2 VIEWS OF M/S. AL KHALEEJ POLYPROPYLENE PRODUCTS COMPANY SAOG, SULTANATE OF OMAN:

ON PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLES:

The product under consideration as stated by the domestic industry and also in the initiation notification is vague and too broad. The contentions of the petitioners as well as the contents of the initiation notification and the preliminary findings amply clarify that the different types of BOPP films are neither technically nor commercially substitutable amongst each other. Therefore, it would not be appropriate to consider all types of BOPP films as like articles under the Anti-dumping Rules.

The exporter has argued that metallised BOPP film should not be treated as like article to the BOPP film because the process of metallising renders a new product, which has a different name, character, and use. In support of this, the exporter has submitted two clarifications from the Central Board of Excise & Customs (copies enclosed) which are based on the judgements of the Hon'ble Supreme court of India and therefore, binding. The exporter has claimed that as per the Supreme Court rulings, Metallised BOPP films are distinct products than the plain BOPP films, there is no question of including the same under a single category. The Metallised BOPP films were not to be a part of the investigations ab initio.

(b) ON STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY:

The exporter has stated that so far as 'standing' is concerned, the Designated Authority has to make a final determination at the time of initiation. This is in contrast to the test of 'sufficiency' as envisaged under Rule 5(3)(b) to justify an investigation. In this case, the Hon'ble Designated Authority has not recorded any determination in the initiation notification. Therefore, the exporter has submitted that the case needs to be terminated in terms of several WTO Panel decisions as this basic flaw cannot be cured now. Further it has been argued that any determination on standing is intrinsically flawed as the description of the product under consideration itself was ambiguous at the time of initiation.

(c) ON PERIOD OF INVESTIGATION :

They have stated that it appears that in this case, the domestic industry had proposed a period of 18 months for detailed examination by the Designated Authority and the same has been accepted by the Hon'ble Designated Authority for reasons not available either in the petition, public file or the preliminary findings. While there is no bar or limitation on the power of the Designated Authority to pick any particular period as the period of investigation, it may not be out of place to mention that the period is generally selected all over the world depending upon certain economic or financial factors. Some of the considerations which may affect the choice of the period of investigation include factors such as financial year, calendar year of the business cycle. Normally the financial year is taken as period of investigation, as it takes into account all the seasonal variations coupled with the administrative convenience. If, however, the Domestic Industry demonstrates that there is a need to take a longer period of investigation, there must be sufficient ground with the Designated Authority to depart from the practice of taking a full accounting year or only certain quarters of the same.

(d) ON INJURY

The injury analysis after taking into account only 47.8% of the Domestic Industry is incorrect particularly when the petitioners themselves acknowledged during the public hearing that the petition has been filed on behalf of the association and that they represent other produces as well.

(f) VIEWS OF M/S ALKHALEEJ ON THE DISCLOSURE STATEMENT :

1. It has been stated in the disclosure statement that 'The materialization process consists of addition of metal, such as aluminum, and the same does not alter the basic physical, technical and chemicals characteristics of polyester film'. This is in direct contrast to the CBEC Circular wherein it has been clearly held that 'conversion of bare films into lacquered, laminated or bare films brings into existence of a new product with distinct name, character and use'.
2. It may be noted that the decision of the CBEC is based on two decisions of the Hon'ble Supreme Court and the opinion of the Law Ministry. It would be extremely surprising if the Hon'ble Designated Authority chooses to rely upon some uncited decision of the EC when the same issue has been categorically decided by the CBEC following the decision of the Hon'ble Supreme Court and the opinion of the Law Ministry.

3. It has also been stated in para 1.7(ii) of the disclosure statement that "The fact that an addition production step is required for production of metallized polyester film (and the same results in higher cost of production and sales price) is not an element which could justify per se exclusion of certain type from the scope of the proceedings". The position in the EC case appears to be different than the case in India. Apparently in the EC case, the issue was of exclusion of METALLIZED FILM. Therefore, the decision of the EC cannot be appreciated unless the claims made in the complaint, scope of the investigation in the initiation notice etc. are made known to the Designated Authority. The arguments made by the Indian exporters also have a direct significance on the issue, a copy of which has not been supplied to us despite request vide our letters dated 9th and 10th of May, 2002. It would be a travesty of justice if some decision of the EC is relied upon in preference to the guidelines of our own Supreme Court without even seeing all the papers and the background of the said EC decision. Notwithstanding the above, it appears that the EC case was different from this case as in the instant case, metalized film were not included from the very start of the case, as would be obvious from the following paragraphs.
4. It was never the intention of the Domestic Industry nor the Designated Authority to include the Metallised BOPP films under the scope of investigation as would be revealed by the following:-
 - (a) In para 4,1,3 of the primarily findings, it has been categorically mentioned that:

"BOPP films is primarily used by the packaging industry , it is used mainly in packaging adhesive tapes..... Metallising,....etc."

It was submitted that the Metallised BOPP films cannot be used for further metallising and, therefore, the films which are already Metallised cannot be considered as a part of the product under consideration.
 - (b) In para 4,1,3 of the Preliminary Findings, it has been mentioned that "BOPP film is produced by extrusion method..... Polypropylene is extruded to obtain BOPP film". Thus, even this part of the product under consideration of the preliminary findings clarified that only extruded products were to be covered and it was never the intention of the Domestic Industry as well as the Hon'ble Designated Authority to include the Metallised BOPP films under the scope of investigation.
 - (c) The fact that the Metallised BOPP films could not have covered from the scope of investigation, is also clear from the determination of the standing of the Domestic Industry to file the petition. It is obvious from plain reading of the petition as well as the preliminary findings that a large number of stand alone metallisers were not considered for the purpose of applying the tests of standing for the Domestic Industry.

According to their information, there are as many as 29 stand-alone metallisers in the country. Even the DEPB rates are different for metallised films. If, however, the Hon'ble Authority considers that Metallised BOPP films were included in the scope of investigation, then, it is submitted that the initial determination of the standing of the Domestic Industry to file the petition itself would be flawed.

(d) It is also interesting to note that in their written submissions, the Domestic Industry has 'clarified' that Metallised BOPP films is within the scope of the petition filed by them. The Hon'ble Designated Authority would be kindly aware that the jurisprudence of anti dumping does not permit enlargement of the scope of investigation. Thus, it is our submission that the above arguments singularly as well as severally establish the fact that Metallised BOPP films were not to be a part of the investigations ab initio.

ON INJURY:

(a) Domestic Industry has been defined in the first part of the definition so as to refer to the domestic producers as a whole engaged the manufacture of the like article and any activity connected there with. It further states, as an alternative, that Domestic Industry can refer to those domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article. We, therefore, submitted that the injury analysis based only on 47.8% is inappropriate as anything less than 50% would not constitute a major proportion. Besides the legality of the issue, we requested the Designated Authority to consider the fact that it would be wholly inappropriate in economic sense to analyze the information of a smaller part of the Domestic Industry to arrive at a conclusion for the entire Domestic Industry. The Designated Authority also needs to go into the financial health of the producers who are merely "supporting; but not a part of the so-called petitioner Domestic Industry. It was in the above context that we had been insisting that the Domestic Industry be compelled to provide full disclosure to enable the Designated Authority to arrive at fair and just findings. This also has a direct bearing on the issue of causal link.

(b) As regards the volume of imports, it was stated in the preliminary findings that the volume of imports from the subject countries had increased in absolute terms further held that in percentage terms also the volume had increased. Similar analysis had been done for market share and landed costs also.

(c) Kindly recall that the exporters had submitted that the figures of the period of investigation cannot be compared to 1997-98 as a proper analysis would require that the comparisons are made with the immediately preceding period unless reasons to the contrary are

demonstrated. That being not the case, the findings of injury on these factors need to be re-looked at as a proper analysis would result into a totally different picture. In addition to the above, exporter drew the kind attention of the Hon'ble Designated Authority to the incorrect presentation of information by the Domestic Industry to arrive at totally skewed results. The Domestic Industry had 'annualized' the 18 month figures apparently to make proper comparisons. The Hon'ble Authority needs to appreciate that when the actual figures of 12 months within the 18 month period are available, only the remaining 6 months ought to have been annualized. We had carried out an analysis after taking the actual figures of 1999-2000 and annualizing the figures of the first six months of the year 2000-2001, both periods being part of the period of investigation. The market share from the subject countries had actually declined from 54.4% to 30.4% during the last six months of the period of investigation annualized). The market share as a percentage of the demand has also come down from 4.2% to 1.2% during the same period.

C. VIEWS EXPRESSED BY IMPOTERS:

2.3 M/S. NEW PACK PLASTIC PVT. LTD:

Due to the initiation of this anti dumping investigation the prices of BOPP Film have been continuously going up though the prices of Poly-Propylene is going down.

The imports of BOPP Film in our country is only 6.37% of the total demand. Such a meager volume of imports cannot be called as dumping of BOPP Film when 93.63% of the Indian demand of BOPP Film is being made by the domestic manufacturers.

In the international market the price of BOPP Film (Tape grade) is about US\$ 1.20 per Kg.(approx. Rs.57.60) and even the Indian Film manufacturers are offering same export price whereas in the domestic market they are offering at a price of Rs.98.00 per Kg.

In view of the above, they have requested that anti dumping duties should not be imposed.

VIEWS OF USER ASSOCIATIONS:

2.4 M/S.PAPER, FILM & FOIL CONVERTERS' ASSOCIATION, BOMBAY:

ON INJURY:

Export prices are not significantly below the prices of Indian product. Production of Indian industry has gone up by 20%.

The profitability of few players including one of the petitioners has gone up dramatically in the year 2000-01 over the period 1999-00.

Almost every player has improved on capacity utilisation. Those who have been able to achieve 70 or more percentage utilisation are making profits. The increased capacity utilisation of Indian Industry has led to increase sale, which profits.

ON STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY:

The petitioner constitutes only 47% of the total production and therefore in terms of Rule 2(b) of Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 {Notification 2/95-cus(N.T.) dt. 1/1/1995}, the petitioner cannot be defined as "domestic industry".

Other users:

Representations have been received are from M/s. Jurgyan Industries, Jabalpur, M/s. Jaipur Tissues, Jaipur, M/s. A.kit Packaging Ltd., Secunderabad, M/s. National Adhesives, New Delhi, M/s. P.G. Industries, Gwalior, Meghana Laminates, Mumbai and M/s. Windsor Packaging Pvt. Ltd., Chandigarh.

In response to the preliminary findings interested parties mainly users of BOPP Film – Self Adhesive Tapes have been representing against imposition of anti dumping duty. In brief following issues have been raised:-

1. Imposition of anti dumping duty has led to increase in price of BOPP Film domestically, though the prices of polypropylene (which is the major raw material for BOPP film) is declining.
2. A clear case of profiteering by BOPP Film manufacturers at the cost of thousands of SSI units.
3. M/s. Gujarat Propack, one of the petitioners has been taken over by M/s. Cosmo Films.
4. Except for petitioners other manufacturers of BOPP Film like M/s. Cosmo Films M/s. Xpro India Limited are making profits.

M/s. Adhesive Tape Manufacturers Association (ATMA)

The users have stated that almost all requirement is being met by Indian manufacturers.

Out of small volume of import of BOPP film compared to total consumption of the country BOPP Film (Adhesive Type grade) would be below 0.4%. This does not show any dumping.

The domestic manufacturers in India have formed a cartel and are raising the sale price of their film continuously.

There are more 250 SSI units of adhesive tape employing thousands of workers. With the imposition of anti dumping duty, the adhesive tape manufacturers would suffer.

M/s. Sanghi Industries Ltd.

The present export market is extremely competitive with respect to BOPP Adhesive tape. Any increase in input cost of adhesive tape will result in becoming uncompetitive in international market.

There is no dumping of BOPP Film in Indian Market.

The domestic BOPP film manufacturers are make bumper profits.

The Government of Hongkong Special Administrative Region, Hongkong

In response to the preliminary findings, the Trade and Industry Department, Government of HKSAR have stated that the volumes of imports from HKSAR, India during the period of investigation were exceptionally larger than the volumes indicated in their own records. Since the the Authority has only provided non-confidential version of the petition, they are deprived of certain crucial information and could not comment further.

Their records illustrate that Hongkong had a very minimal amount of export of BOPP Films to India besides Hongkong is a separate customs territory. Commodities from allover the world could be routed through HongKong freely. These free exports could however, not be separated from their own exports. Hence they are unconvinced regarding sufficient evidence on dumping.

M/s. Oman Plastic Industries IIC

The company has stated that they are not manufacturing BOPP Film and are not exporting to India.

M/s. Toyo Packaging Industries Pvt.Ltd., Singapore

The company has stated that they have not done any business with India for the past five years.

M/s. P.T.Trias Sentosa Tbk, Singapore

The company has stated that they are the exporters of BOPP Film and other packaging flexible film all over the world including India.

They have also stated that there is no dumping of BOPP Film to India as currently BOPP film is in short supply. Therefore, there is no reason of selling the products at dumped prices by exporters.

They have also indicated that the filling up of the questionnaire is time consuming and have not furnished the information in the form and manner prescribed by the Authority.

M/s. PT Inamuti Intipack, Jakarta.

The company has stated that they have never exported BOPP products to India. Further, they have stated that they have never produced or sold BOPP products domestically or internationally.

Examination by the Authority:

- 2.5 On Domestic Industry: The Designated Authority is required to "determine" that the petition has been made by or behalf of the domestic industry. However, such "determination" is not stated to be the final determination.

Proviso to the Rules very clearly stated that the investigations can be initiated in case of producers expressing supporting the petition account for more than 25% of total production. Thus, this Rule very clearly implies that the case can be initiated, if the producers supporting the petition and participating in the investigation as petitioner companies command more than 25% of Indian production. Such being the case, the whole argument is without merit.

- 2.6 On investigation period: The Authority notes that the investigation period in the instant case is 18 months (April, 99 – Sept., 00). Thus, the Authority is required to examine the performance of the domestic industry in the investigation period with reference to previous periods. It would not be appropriate to annualize the figures for the period April-Sept., 00 and then compare with 1999-00, as 1999-00 itself forms part of the investigation period. Since the investigation period is of 18 months, it would be more appropriate to annualize the data for the investigation period and then compare with the previous years. In an alternate, such comparison could have been done by reducing all figures to monthly averages. However, this also would not have materially altered the position.

While the Authority holds that comparison of investigation period with previous years is the requirement under the Rules and consistent practice of the Authority.

The Authority notes in this regard that it would not be appropriate to base entire comparison to immediate preceding year. The practice of the Authority is to do comparisons over a period of time.

3. The submissions made by the petitioners, exporters, importers and other interested parties have been examined and issues raised with reference to the rules and having a bearing on this case have been considered and dealt with at appropriate places in the notification.
- D. **DISCLOSURE OF ESSENTIAL FACTS MADE BY THE AUTHORITY:**
4. The views raised in response to the disclosure statement are discussed in the present findings to the extent these are relevant as per rules and have a bearing on the case.
- E. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION:**
5. The product involved in the present investigation is Biaxially Oriented Poly Propylene Film (BOPP) (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Oman, UAE, Singapore and Thailand. Biaxially Oriented Poly Propylene Film (BOPP) is a high performance biaxially oriented, special film made from Polypropylene. BOPP Film is produced in a wide variety of forms and types which are employed for a large range of end-use applications. BOPP Film is produced on various types of production lines, which are differentiated by a number of technical features including the Film thickness and width, the feeding process and the formula of fillers, the production environment conditions as well as certain specific capabilities such as on-line coating or co-extrusion mainly depending on the combination of the capabilities BOPP Film can be commodity-type or specialty type.

Biaxially Oriented Poly Propylene Film (BOPP) is classified under Customs heading No. 3920.20 of schedule 1 of the Customs Tariff Act, 1975 and No.3920.2000 under Indian Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System) originating from subject countries. The classification is however, indicative only and in no way binding on the present classification.

The Authority notes that the product under consideration in the present investigation is Biaxially Oriented Poly Propylene Film. Such BOPP Film is produced by extrusion of Polypropylene. Once this base film is produced, it can then be processed further (such as metallisation) to enhance some of its properties. However, the basic physical, technical and chemical characteristics of the product remains the same and is also used for packaging. It is also noted that the investments required for production of base film and for metallising such base film further reinforces the fact that Metallised BOPP Film is one of types of BOPP Films. The Authority notes that investigations were earlier conducted in respect of Polyester Films wherein metallised polyester films and plain polyester films were treated like articles..

The Authority further notes that the scope of the investigations has not been enhanced by including Metallised BOPP films. Such BOPP films were included in the petition. Even the calculations of export price, normal value, dumping margin, and information relating to injury provided by the petitioners included Metallised Films. This is also evident from the fact that Metallised BOPP Films and Plain Films fall under same customs classification and information with regard to imports and import price was based on the data compiled by the DGCI&S, Calcutta.

With regard to the circulars of CBEC and the orders of Hon'ble Supreme Court, it is appreciated that metallising plain film constitutes production within the meaning of Excise and Customs. However, the purpose of determination of "industry" for the present purpose is altogether different than the purpose for which production is recognized in Excise and Customs. Production for the purpose of Excise or Customs Duty and production for the purpose of anti-dumping investigations can not be equated. The Authority notes in this connection that CBEC Letters no. 93/75/86-CX3 dated 9-10-1986 and Circular no. 5/89 dated 10-1-1989 are for the purpose of collection of excise duty or CVD and rates thereof, whereas the meaning of production in the present context is altogether different. For the present investigations, only those producers who undertake basic production activity (i.e., making of base BOPP Films) are recognised as producers. Those producers who are carrying out incidental activities, such as metallisation, can not be regarded as producers for the present purpose.

In view of the above, the Authority holds that the scope of the present investigations extends to all types of BOPP Films, including Metallised BOPP films.

F. LIKE ARTICLES:

6. Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules specifies that "Like Articles" means an Article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an Article, another article, having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

In view of the explanation in para..., the Authority confirms the Preliminary Findings on Like Article.

G. DOMESTIC INDUSTRY:

7.1 As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry."

7.2 The definition of domestic industry given above is further clarified by Rule 5 of Rules which reads as follows:-

"----- the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition as the case may be to the application.

7.3 The petition has been filed by BOPP Film Producers Association, New Delhi on behalf of domestic industry. The petitioners alongwith supporters account for a major proportion of total Indian production and therefore have a standing to file the petition on behalf of domestic industry under the Rules above said.

	Prod.(in MT) during POI	% Share
Petition with supporters (Members of Association)	54161	92
Others (Non Members)	4695	8
Total Indian production	58856	100

The Authority notes that the petition in the instant case was filed by the Association of BOPP producers. There is no opposition to the petition. The participating companies constituted more than 25% of Eligible Indian Production at the time of initiation. Further, the petitioners alongwith the supporters constituted more than 50% of Eligible Indian Production. Thus, there is no basis for the argument that the petition did not satisfy standing at the time of initiation. Subsequent to initiation, the petition has been specifically supported by Max and Supreme. Thus, the petitioner satisfies the requirement of standing.

**H. THE NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN:
DUMPING MARGIN-COMPARISON OF NORMAL VALUE AND
EXPORT PRICE:**

- (a) The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

- (b) The views of the Domestic Industry, Exporters, Importers and other Interested parties with regard to the Dumping Margin have been dealt with in para 2 above and have not been reproduced here for the sake of brevity.
- (c) The Authority has followed the provisions governing determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I of Anti-Dumping Rules and the practice being followed in this regard. Based on the Normal Value and Export Price, determined as explained above, the Authority has worked out the Margin of Dumping.

8.0 NORMAL VALUE:

**8.1 M/S. AL KHALEEL POLYPROPYLENE PRODUCTS COMPANY SAOG, SULTANATE
OF OMAN:**

- i) M/s Al Khaleel has responded in the investigation after the Preliminary findings.
- ii) BOPP film is a process industry and it generates a wide spectrum of product quality. The film rolls are graded as A grade (prime/first), B grade(second) or re-processable. All producers in the world sell the B grade films in addition to prime quality. India is a very cost conscious market and users in India seek the 'B' grade film.
- iii) 'B' grade films are sold at price around 40-50% cheaper than 'A' grade film. The price of 'B' grade film should be compared with price of 'B' grade and not with 'A' grade.
- iv) They have stated that the Indian BOPP industry already has sufficient protection in form of import duties.
- v) They have indicated that the domestic prices as compared to average selling price in India is higher due to reasons like short lead time, just in time delivery and small lots and open payment terms which means higher risk.

- vi) They have also stated that they do not keep grade-wise accounts and costing data. Hence, combined information for all grades have been furnished.
- vii) Even though the exporter has stated specifications in the transaction-wise statements, the same have not been explained anywhere in the response.

The response filed by the exporter has been analyzed in detail. Average selling price as per transaction wise statement in the domestic market as per the sale price structure statement comes to **** RO per MT. The company has claimed the cost of production as **** RO per MT. The data as presented by the exporter has been analysed as under:

- (a) Ex-factory selling price has been determined for each transaction in the domestic market. Such selling price has been compared with Ex-factory cost of production claimed by the company.
- (b) This analysis shows that the exporter has made losses in respect of 30% of its domestic sales. Para-2 (i) of Annexure-I to Anti Dumping Rules under Customs Tariff Act, 1975 provides that when the volume of sales below per unit costs represent not less than 20% of the volume in transaction under consideration the Designated Authority may disregard the sales in determining normal value.
- (c) Ignoring the loss making sales it is found that the weighted average selling price at ex-factory level in respect of exporter for profitable domestic sales the Authority determines the normal value at US\$ **** per Kg.

8.2 OTHER EXPORTERS FROM SUBJECT COUNTRIES:

None of the other exporters/producers in subject countries have responded to the Authority in the form and manner prescribed. The Authority determine normal value on the basis of the constructed cost of production, considering the best information available on record at US \$ *** per Kg.

8.3 EXPORT PRICE:

M/S. AL KHALEEL POLYPROPYLENE PRODUCTS COMPANY SAOG, SULTANATE OF OMAN:

M/s. Al Khaleej Polypropylene Products Company SAOG, Sultanate of Oman, one of the exporters, has furnished information relevant to determination of export price. The exporter has provided details of exports made to India during Period of Investigation (POI) for both A grade as well as B grade films though majority sales are of B grade films. The exporter has however claimed export price based on sale of

A Grade after excluding sale of B grade BOPP films to India. The exporter has not indicated any reason or justification for such classification and exclusion thereof. The exporter has also acknowledged that they do not keep any grade wise accounts and cost data. In view of the above, it is proposed to consider all exports to India for arriving at the Export Price. Adjustments as claimed by exporter on account of overseas freight and overseas insurance etc. have been considered. This Authority determines export price at US\$**** per MT.

8.4 OTHER EXPORTERS FROM SUBJECT COUNTRIES

In respect of all other exporters from subject countries, the Designated Authority proposes to arrive at ex-factory export price based on the information provided by the petitioners as per the information compiled by DGCI&S, Calcutta. In order to arrive at the ex-factory export price the petitioners have claimed adjustment with regard to ocean freight, Landing charges Marine insurance, commission etc. The same has been proposed to be considered.

- 8.5 The Authority holds that the exporter M/s Al Khaleez has not adduced any evidence to justify separate treatment of the two grades. Further, the exporter admits that it does not maintain separate records for the two grades. It more appropriate to combine the information for the two grades.

8.6 DUMPING MARGIN

The Authority proposes to follow the consistent policy of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I of Anti- Dumping Rules.

<u>Subject Country</u>	<u>Exporters</u>	<u>Normal value In</u>	<u>Export price US\$</u>	<u>Dumping margin Per Kg.</u>	<u>DM as % of EP</u>
Taiwan	All Exporters	***	***	***	73.68
Hong Kong	All Exporters	***	***	***	61.77
Indonesia	All Exporters	***	***	***	72.57
Oman	M/s Al Khaleej	***	***	***	28.77
	Other Exporters	***	***	***	47.86
Singapore	All Exporters	***	***	***	81.48
Thailand	All Exporters	***	***	***	88.54
UAE	Deminimus Imports	***	***	***	-

203062102-8

I. INJURY AND CAUSAL LINK:

- 9.0 The Authority has taken into account all indices regarding injury in the final determination. This involved examination of all relevant parameters, as laid down under Principles for Determination of Injury specified under Annexure 11 to the Anti Dumping Rules. The Authority has examined (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Authority, for the purpose, considered whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In order to examine the effect of the dumped imports on prices the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports was otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree. The effect of dumped imports on the domestic industry has been examined by considering the parameters such as decline in sales (actual or potential), production, capacity utilisation, market share, productivity, stocks, selling prices, profitability, return on investments, the magnitude of the margin of dumping, cash flow (actual and potential), employment, wages, growth, ability to raise funds, etc. for the domestic industry. The Authority has carried a detailed examination of the domestic industry to arrive at non-injurious price. While determining the non injurious price, the Authority has done appropriate analysis of the relevant factors such as usage of raw material & utilities, expenses incurred by the domestic industry during the period of investigation,

Injury to the domestic industry was based on two petitioner companies, M/s. Flex and Gujarat Propack for the purpose of preliminary findings. However, M/s. Supreme and Max have provided costing and injury information after the preliminary findings. The Authority has considered it appropriate to include this information for the purpose of injury assessment. Accordingly, these findings on injury are based on four companies.

It is clarified that the injury and costing information by M/s Max and M/s Supreme has been provided after the oral hearing and a non confidential version thereof was placed in the public file.

- 9.1 Investments and capacity utilisation.: The Non-Injurious Price for the domestic industry has been determined considering a reasonable return on the capital employed by the participating and supporting companies. For calculation of injury margin, the wt average ex-factory non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject goods.

9.2 Imports Volume :

The volume of Imports from subject countries is above de minimis except in respect of UAE. The Authority notes that the volume of imports from UAE is 2.6% that is below de minimis level of 3%. The volume of imports from UAE during the period of investigation is de minimis and therefore the Authority does not consider appropriate to recommend anti dumping duty with respect to imports from UAE. In the circumstances, the country UAE is taken out of the purview of this anti dumping investigations and the preliminary findings confirmed.

9.3 Volume of Imports and Market Share:

Country	in Kg					
	<u>1997-98</u>	<u>1998-99</u>	<u>1999-00</u>	<u>4/00 to 9/00</u>	<u>POI</u>	<u>POI Annu</u>
Subject Countries	205472	637974	1775323	275725	2051048	1367365
Other Countries	846445	1411910	1490639	632384	2123023	1415349
Total Imports to Country	1051917	2049884	3265962	908109	4174071	2782714
Sale of Indian Producers	35248000	39973000	39341000	21991000	61332000	40888000
Demand in the Country	36299917	42022884	42606962	22899109	65506071	43670714
Share of Subject Country in Total Imports (%)	19.5%	31.1%	54.4%	30.4%	49.1%	49.1%
Market Share in Demand						
Subject Countries	0.6%	1.5%	4.2%	1.2%	3.1%	3.1%
Other Countries	2.3%	3.4%	3.5%	2.8%	3.2%	3.2%
Indian Industry	97.1%	95.1%	92.3%	96.0%	93.6%	93.6%
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

As seen from the above, the volume of imports from subject countries (i.e. excluding UAE) have increased in absolute terms during POI (Annualised) over the year 1997-98. In percentage terms also the volumes have increased from 19.5% in 1997-98 to 49.1%. The market share in demand of subject countries which was at 0.6% in 1997-98 has increased to 3.1% during POI and the share of domestic industry has declined from 97.1% to 93.6% during the same period.

9.4 Production

The production of the participating companies and supporting companies has increased over the period. However, increase in production has to be seen alongwith commencement of production by M/s Flex Industries and the cost of production and sales realization of the domestic industry. Though, the production increased, the industry was not able to sell its produce at a price which permit even recovery of full cost of production. Therefore, the increase in production has resulted in increase of its losses.

9.5 Capacity Utilization

The capacity utilisation of the domestic Industry has increased. As mentioned in the previous para, though the production increased, the industry was not able to sell its produce at a price which permit even recovery of full cost of production.

9.6 Sales

The sales of the participating /supporting units have increased over the period. Further, the production and sales volume are directly related to cost of production and sales realization. Export Price from the subject countries have declined resulting in lowering the landed value due to which the sales realisation could not reach upto a fair level.

9.7 Landed Price of imports & Selling Price of domestic industry:

The landed price has been declining over the past years. The selling price has also been declining over the past years disproportionate to the changes in cost of production of the subject goods. A comparison of sale price and the landed price of subject goods, it is noted that the participating companies increased the prices in 1999-2000, the same was due to steep increase in the cost of production. However, the increase in the cost of production was more than the increase in the selling price during the period of investigation.

The dumped imports from the subject countries are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the Indian market.

9.8 Employment

The employment level in the participating companies/supporting companies has not undergone any significant change due to poor operating levels.

Examination by Authority regarding injury to domestic industry:

9.9 With regard to the argument that the participating companies command less than 50% of Eligible Indian Production, the Authority notes that there is no legal basis to state that the injury to the domestic industry must be examined in respect of those producers who command more than 50% of Indian Production.

9.10 The Authority further notes that merely because Association has filed the present petition, it does not imply that the Authority is bound to consider information in respect of all Members of the Association. The Authority considers that the participating companies command more than 25% of Indian Production. Further, the support by the Association after a decision by the Executive Committee of the Association implies that the members of the Association are supporting the petition. Thus, the Authority considers that the participating companies' alongwith supporters are more than 50% of Indian Production.

Max and Supreme have provided injury information after the preliminary findings. The Authority has included this information also for assessment of injury. Thus, the injury to the domestic industry in the present findings has been assessed for those producers who command more than 50% of Eligible Indian Production.

9.11 Conclusion:

The following parameters prima facie indicate that the injury to the domestic industry has been caused from the dumped imports:

- The volume of Imports from the subject countries have increased significantly and a direct consequence the domestic industry was not in a position to increase its selling price to a fair level;
- The market share of imported goods from subject countries has gone up;
- The decline in the Export Price by the exporter in the Indian market has directly resulted in the decline in the landed value from the subject countries;
- The dumped imports from the subject countries are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the Indian market.
- The domestic industry is finding it difficult to increase the selling prices to optimum level;
- The domestic industry has been forced to sell below cost of production. This has directly resulted in severe financial losses to the domestic industry.
- The volume of imports from UAE during the period of investigation is de minimus.

In view of the above, Authority concludes that the material injury to domestic industry has been caused by the dumped imports from subject countries other than UAE.

J CAUSAL LINK

- 10.1 The imports from the subject countries are being made at dumped prices. The imports from other countries are at much higher prices or the volumes are de minimus. Imports from other countries are, therefore, not causing injury to the Indian industry.
- 10.2 The demand of the BOPP Film in India is more or less constant. The domestic industry has sufficient capacity to meet the entire demand of BOPP Film in India. Therefore, the changes in demand have not caused any injury to the Indian industry.

- 10.3 Petitioners have reiterated that the BOPP Film industry in India is not so old as to have suffered any injury on account of the developments in the technology. The industry has employed the latest available technology and constant efforts are made to update the same. In fact, India is a major exporter of BOPP Film to developed countries, where production facilities also exists.

11.0 PRICE UNDERTAKING

- 11.1 Rule 15 relating to Suspension or termination of investigation on price undertaking provides that the designated authority may suspend or terminate an investigation if the exporter of the article in question furnishes an undertaking in writing to the designated authority to revise the prices so that no exports of the said article are made to India at dumped prices, or in the case of imports from specified countries undertake to revise the prices so that injurious effect of dumping is eliminated and the designated authority is satisfied that the injurious effect of the dumping is eliminated.
- 11.2 One of the exporters, M/s. Al Khaleej Polypropylene Products Company SAOG, Sultanate of Oman (Al Khaleej) had extended its willingness to offer price undertaking. The offer was examined in detail and the Designated Authority found that the undertaking offered by the exporter can be accepted since it eliminates the injurious effect of dumping. The exporter has agreed to provide all reasonable information which the Designated Authority considers relevant and necessary. The Designated Authority has accepted Price Undertaking from the exporter and accordingly no duties would apply in the case of exports of all types of BOPP films, from this company. However, in the case of any violation in the execution of this undertaking by the exporter, the duties, as set out in the preliminary findings, would provisionally apply, pending specific recommendations by the Designated Authority in this regard. It is also clarified that this undertaking would apply only in case of exports made by this company directly to India. In case the goods are exported by some other company, the residual duty, as mentioned below, would apply, even if the same are the produce of this company.
- 11.3 The company has extended one price undertaking for all types of BOPP film exported by them. The undertaking amount is at US \$ 1.63 per Kg of BOPP film. The undertaking price is the minimum CIF value of imports.

K INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES:

12.1 The purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the petitioner companies/ domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

12.2 It is recognized that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of anti dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the petitioner company. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the petitioner companies and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

12.3 To ascertain the extent of anti dumping duty necessary to remove the injury to the petitioner companies, the Authority has relied upon non injurious selling price of BOPP film in India for the petitioner companies and supporting companies, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilisation for the petitioner companies.

M CONCLUSIONS:

13.0 The Authority, after considering the foregoing, concludes that:

- (a) BOPP film originating in or exported from the subject countries has been exported to India below its normal value, thereby resulting in dumping.
- (b) The domestic industry has suffered material injury.
- (c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from subject countries.

14.0 The Authority, after considering the foregoing, concludes that:

- (a) The Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of BOPP Films falling under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, originating in or exported from Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Oman, Singapore and Thailand.
- (b) The Authority considered recommending the amount of Anti-Dumping Duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to domestic industry. The average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the Non-Injurious selling price of the petitioner, supporting companies, determined for the period of investigation. Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended.
- (c) Accordingly, the Authority confirms the preliminary findings with regard to imposition of anti-dumping duty and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of BOPP film falling under the Chapter 39 of Customs Tariff Act. Originating in or exported from subject countries. However, no duty would apply in case of exporter from M/s Al Khaleej, Oman wherein Authority has accepted the price undertaking given by the company. The anti dumping duty shall be the amounts mentioned in column (3) below :

<u>Subject Country</u>	<u>Name of the Exporter /s</u>	<u>Amount of anti dumping duty in US \$ per Kg</u>
(1)	(2)	(3)
Taiwan	All Exporters	0.70
Hong Kong	All Exporters	0.63
Indonesia	All Exporters	0.52
Oman	M/s Al Khaleej	No Duty —covered under price undertaking
	Other Exporters	0.47
Singapore	All Exporters	0.60
Thailand	All Exporters	0.79

15. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 or 9A, as the case may be, of the Customs Tariff Act, 1975.
16. Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 14.8.2001
17. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

